श्रावण शुक्ल - 1 ■ संवत 2082 ■ वर्ष - 21 ■ अंक - 3 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » शुक्रवार » 25-07-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 कांग्रेस की नई पीढ़ी के संस्कार देश देख रहा है : बिरला

6 कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?

7 मैं अपने ही घर में उत्पीड़न का शिकार : तनुश्री दत्ता

फर्स्ट टेक

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन का एक डिब्बा विस्फोट से क्षतिग्रस्त

पेशावर/भाषा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बृहस्पतिवार को हुए विस्फोट में क्वेटा जाने वाली एक यात्री ट्रेन का एक डिब्बा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मार्च के बाद से यह इस तरह का तीसरा हमला है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के कारण किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर मुर्तजा खान ने सिबी में संवाददाताओं से कहा, प्रांत के सिबी जिले में बख्तियाराबाद और डंबोली इलाकों के बीच रेलवे पटरियों को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया, जिसके कारण कराची से क्वेटा जा रही बोलन मेल प्रभावित हुई। उन्होंने इसे आतंकवादी कृत्य करार दिया। उन्होंने बताया कि घटना में ट्रेन का कोच संख्या सात आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन सुरक्षित सिबी रेलवे स्टेशन पहुंच गई।

अगर अमेरिका विश्वास बहाली के कदम उठाता है, तो हम परमाणु वार्ता के लिए तैयार हैं : ईरान

तेहरान/एपी। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम घरीबाबादी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वह विश्वास बहाली के लिए सार्थक कदम उठाएगा। ईरान शुक्रवार को इस्तांबुल में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तथा यूरोपीय संघ के उप विदेश नीति आयुक्त के साथ बैठक करने वाला है। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद यह पहली वार्ता होगी। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। घरीबाबादी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वार्ता में शामिल होने के लिए, ईरान ''कई प्रमुख सिद्धांतों'' को बनाए रखने की मांग कर रहा है।

रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 48 लोगों की मौत

मॉस्को/एपी। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में हुई विमान दुर्घटना में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। अमूर क्षेत्र के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि एएन-24 यात्री विमान रूस-चीन सीमा पर स्थित ब्लागोवेशचेंस्क शहर से तिंडा शहर की ओर उड़ान भरते समय रडार से गायब हो गया था। इसमें कहा गया है कि बाद में बचावकर्मियों को घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी पर विमान का जलता हुआ मलबा मिला।

25-07-2025 सूर्यास्त 6:48 बजे | 26-07-2025 सूर्योदय 6:04 बजे

BSE	NSE
82,184.17	25,062.10
(-542.47)	(-157.80)

सोना	चांदी
10,284 रु.	116,534 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

नव राजवंश

राजतंत्र के दोषों का,
अब भी चुभता है हृदय दंश।
डेमोक्रेसी में उदित हुए,
सत्तागामी नव राजवंश।
जो काबिल या नाकाबिल हैं,
पर हैं नेता के बीज अंश।
सत्ता पद पाने जो येनकेन,
करते रहते विध्वंश-ध्वंश।।

भारत-ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता

■ इस समझौते के तहत 99 प्रतिशत उत्पाद श्रेणियों के पूरी तरह शुल्क-मुक्त होने से भारत को फायदा होगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लंदन/भाषा। भारत और ब्रिटेन ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं ब्रिटिश कारों एवं व्हिस्की जैसे उत्पादों पर शुल्क कम होंगे। अगले साल से लागू होने वाले इस समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करना है जो फिलहाल 56 अरब डॉलर है।

भारत ने चॉकलेट, बिस्कुट एवं सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है। इसके साथ ही उसे कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, खेल के सामान और खिलौनों जैसे निर्यात उत्पादों तक भी आसान पहुंच मिलेगी।

अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते के तहत 99 प्रतिशत उत्पाद श्रेणियों के पूरी तरह शुल्क-मुक्त होने से भारत को फायदा होगा। यह छूट लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य को समाहित करती है।

इसके अलावा, ब्रिटेन में काम कर रहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस जैसी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारत से आने वाले कर्मचारियों के लिए तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी नहीं करना होगा।

इस समझौते को आधिकारिक तौर पर 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (सीईटीए) का नाम दिया गया है। इसे तीन साल तक चली बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर भी मौजूद थे।

स्टार्मर ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए कहा, ''मैं इस समझौते को दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक दिन मानता हूं। यह एक-दूसरे से की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का दिन भी है।''

प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को 'हमारी साझा समृद्धि का खाका' बताते हुए कहा कि ब्रिटेन एवं भारत 'स्वाभाविक साझेदार' हैं और दोनों देश अपने इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते के बाद भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाज़ार मिलेगा और कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे।

मोदी ने कहा, ''यह समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। दूसरी ओर, ब्रिटेन में बने चिकित्सा उपकरण और वैमानिकी उपकरण जैसे उत्पाद भारत के लोगों एवं उद्योगों तक किफायती एवं आकर्षक कीमत पर पहुंच सकेंगे।'' उन्होंने बताया कि दोनों देश एफटीए के साथ 'दोहरे अंशदान समझौते' (डीसीसी) पर भी आम सहमति पर पहुंचे हैं। इससे दोनों देशों के सेवा क्षेत्रों, खासकर प्रौद्योगिकी और वित्त, में नई ऊर्जा का संचार होगा।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं: भारत-ब्रिटेन

लंदन/नई दिल्ली/भाषा। भारत और ब्रिटेन ने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं है और उग्रवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग नहीं करने दिया जायेगा।

ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लंदन में अपने समकक्ष कीर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य में कहा कि लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को ही कमजोर करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए ब्रिटेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा , हम एकमत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि उग्रवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को ही कमजोर करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के भारत प्रत्यर्पण में ब्रिटेन से सहयोग मांगा

लंदन/भाषा। भारत द्वारा ब्रिटेन से भगोड़े कई आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दोनों पक्षों की संबंधित एजेंसियां इस मामले में 'निकट' समन्वय और सहयोग के साथ काम करना जारी रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष केअर स्टार्मर से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की। मोदी ने मीडिया को दिये वक्तव्य में कहा, ''आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण के मामले में भी हमारी एजेंसियां निकट समन्वय और सहयोग के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगी।''

भारत ब्रिटेन के समक्ष विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाता रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए ब्रिटेन से सहयोग मांगा।

वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में

उच्चतम न्यायालय ने 12 दोषियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

■ पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

■ शीर्ष अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लंबित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

उच्च न्यायालय ने सोमवार 21 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया था। उसने विशेष मकोका अदालत के वर्ष 2015 के फैसले को पलटने हुए उसके उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पांच आरोपियों को मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मकोका अदालत ने कमाल अंसारी (अब मृत), मोहम्मद फैसल शेख, एहते-शाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई थी।

अदालत ने तनवीर अहमद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई, 2006 को सात बम विस्फोट हुए थे। इस घटना में 189 लोग मारे गए थे और 820 लोग घायल हुए थे।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज

■ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि आयोग संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है और उसने कर्नाटक में चुनावी गड़बड़ी होने दी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी किए जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और धमकी भरा बताया है।

आयोग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कुछ तथ्यों को सभी भारतवासियों को जानना चाहिए। उसके अनुसार, कर्नाटक की मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक भी अपील दायर नहीं की गयी जो एक वैध कानूनी उपाय था।

आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया को लेकर दायर 10 चुनाव याचिकाओं में से एक भी चुनाव याचिका हारने वाले किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की, जबकि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत उपलब्ध एक कानूनी उपाय था। आयोग कहा वह यह सोचने पर मजबूर है कि इस प्रकार के आधारहीन और धमकीपूर्ण आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब क्यों लगाये जा रहे हैं?

गांधी ने आज आरोप लगाया था कि आयोग संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है और उसने कर्नाटक में चुनावी गड़बड़ी होने दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वैसे काम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए।

रेणुकास्वामी हत्याकांड :

अभिनेता दर्शन की जमानत के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

बेंगलूरु/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष अदालत ने कुछ आरोपियों की ओर से पेश वकीलों से एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने उक्त फैसले में दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत दी थी।

सरकार अगस्त के अंत तक पेट्रोल में 27 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के मानदंड लाएगी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अगस्त के अंत तक पेट्रोल में 27 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के मानदंड लागू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में 20 प्रतिशत एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत की थी। गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत पहले ही 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है। ब्राजील में, गैसोलीन में एथनॉल मिश्रण 27 प्रतिशत है। वर्तमान में, वाहन इंजन मामूली संशोधन के साथ ई20 (ईंधन में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण) पर चल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वर्तमान में, भारत में ई27 ईंधन के लिए मानक मानदंड नहीं हैं...ई27 के मानदंडों को अगस्त के अंत से पहले अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारत अपनी 85 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतों को आयात से पूरा करता है। उन्होंने कहा, हम 22 लाख करोड़ रुपये मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं, जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है।'' गडकरी ने कहा कि 11 वाहन कंपनियों ने 'फ्लेक्स-फ्यूल' इंजन से चलने वाले वाहन बनाए हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों को पारंपरिक ईंधन के साथ एथनॉल के मिश्रण पर, या यहां तक कि 100 प्रतिशत एथनॉल पर भी चलने के लिए डिजायन किया गया है।

नासा ने नए ऊष्मा स्रोत ईंधन का किया परीक्षण

वाशिंगटन डीसी/भाषा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी से लाखों मील दूर अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए ऊष्मा स्रोत ईंधन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी से लाखों मील दूर गहरे अंतरिक्ष में अज्ञात चीजों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यान में पर्याप्त शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। नासा के रेडियोआइसोटोप पावर सिस्टम (आरपीएस) इन अभियानों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प हैं और इनका उपयोग 60 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है जिसमें एजेंसी के वॉयेजर अंतरिक्ष यान और पर्सिवियरेंस मार्स रोवर भी शामिल हैं।

सहकारिता नीति अर्थतंत्र को करेगी मजबूत : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण करने के बाद कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और सहकारिता के मार्ग पर चलने से देश का अर्थतंत्र मजबूत होगा।

शाह ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सहकारिता मंत्रालय की अनेक उपलब्धियां रही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज देश की छोटी से छोटी सहकारी इकाई का सदस्य गर्व के साथ खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का शुभारंभ हुआ है। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने सहकारिता नीति में बनायी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार थी और आज भाजपा सरकार द्वारा दूसरी सहकारिता नीति लाई गई है। उन्होंने कहा कि जो सरकार के दृष्टिकोण को, जो भारत को, उसके विकास को, और भारत के विकास के लिए आवश्यक सभी कारकों को समझता है, वही सहकारी क्षेत्र को महत्व दे सकता है। यदि देश और अर्थव्यवस्था की मूल इकाई समृद्धि रोजगार देने वाली हो तो वह आर्थिक मॉडल कभी विफल नहीं हो सकता। शाह ने कहा कि सहकारिता नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि नीति का केंद्र बिंदु व्यक्ति, गाँव, कृषि, गाँव की महिलाएँ, दलित, आदिवासी हों। इसका विज़न सहकारिता की समृद्धि के माध्यम से 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। इसका मिशन पेशेवर, पारदर्शी, तकनीकी, ज़िम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सफल लघु सहकारी इकाइयाँ विकसित करना है। हम हर गाँव में कम से कम एक सहकारी संस्था के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

चोट के बावजूद पंत ने जड़ा अर्धशतक, भारत 358 रन पर सिमटा

मैनचेस्टर/भाषा। ऋषभ पंत ने चोटिल होने के बावजूद मैदान पर उतरते हुए अर्धशतक जड़ा लेकिन भारत की पहली पारी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को दूसरे सत्र में 358 रन पर सिमट गयी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 72 रन देकर पांच विकेट और जोफ्रा आर्चर ने 73 रन पर तीन विकेट लिए। भारत ने दूसरे दिन वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत के साहस की बदौलत 350 से अधिक का स्कोर खड़ा कर लिया। भारत का इस सीरीज़ में ये छठा 350+ स्कोर है और एक सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से ये सर्वाधिक है। इंग्लैंड की ओर से सबसे सफल गेंदबाज उनके कप्तान बेन स्टोक्स रहे जिन्होंने पंजा निकाला। भारत ने कल के चार विकेट पर 264 रन से आगे खेलना शुरू किया। रवींद्र जडेजा अपने खाते में एक रन जोड़कर 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने शार्दुल ठाकुर (41), ऋषभ पंत (नाबाद 39) और वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 20) रनों संघर्षपूर्ण पारियों के दम पर लंच तक छह विकेट पर 321 रन बना लिये थे। आज सुबह के सत्र में भारत ने भी कल के स्कोर में मात्र दो रन जोड़े थे कि इंग्लैंड ने नई गेंद जोफ्रा आर्चर को थमाई और उन्होंने रवींद्र जडेजा को अपना शिकार बना लिया।

'मातृछाया' ने आचार्य पाठशाला में जरूरतमंद युवतियों के लिए 10 सिलाई मशीनें भेंट की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। 'मातृछाया' जैन महिला संगठन ने एनआर कॉलोनी स्थित आचार्य पाठशाला एज्यूकेशनल ट्रस्ट को 10 सिलाई मशीनें भेंट की। अध्यक्ष ललिता नागोरी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि कौशल प्रशिक्षण देकर शिक्षा के साथ कमाई करने की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10 सिलाई मशीनें भेंट की गई हैं। मार्गदर्शिका त्रिशला कोठारी ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। हम चाहते हैं कि ये छात्राएं केवल शिक्षा में ही नहीं, बल्कि कौशल में भी अग्रणी बनें।

अतिथि ललिता सिंघवी, लता बोहरा, संगीता सेठिया ने मातृछाया के मानवसेवी कार्य की सराहना की। आचार्य पाठशाला एज्यूकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ विष्णुभरत एवं सचिव प्रकाश ने 'संस्था को धन्यवाद दिया। सचिव रेशमा बड़ोला ने बताया कि इन सिलाई मशीनों के उद्घाटन के साथ ही छात्राओं के लिए कॉलेज द्वारा निःशुल्क फैशन डिजाइनिंग कोर्स प्रारम्भ किया जाएगा। प्रधानाचार्य ने कहा कि इन सिलाई मशीनों का पूरा उपयोग हो इसलिए इसे हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में ही जोड़ेंगे एवं प्रति तीन माह में सिलाई मशीन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस मौके पर कोषाध्यक्ष पुष्पा बाफना, प्रोजेक्ट संयोजिका कविता जैन निर्मला दांतेवाड़िया, पुष्पा सोनीगरा हेमाबंदा, त्रिशला दांतेवाड़िया, पुष्पा नागोरी सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित थीं।

भारत-ब्रिटेन एफटीए देश के उभरते व्यापार ढांचे में मील का पत्थरः उद्योग जगत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय उद्योग जगत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह भारतीय निर्यातकों के लिए परिवर्तनकारी पल है और इससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से 2030 में दोगुना होकर 120 अरब डॉलर का हो जाएगा।

उद्योग जगत ने ऐतिहासिक एफटीए का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमिता के लिए अधिक रोजगार तथा अवसर पैदा होंगे। एफटीए से ब्रिटेन को 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क कम हो जाएगा, जबकि ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत को व्हिस्की, कार और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा।

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने भारत-ब्रिटेन एफटीए पर कहा कि यह भारतीय नितायिकों के लिए परिवर्तनकारी पल है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से 2030 में दोगुना होकर 120 अरब डॉलर का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन मुक्त एफटीए प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से एमएसएमई और श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए अभूतपूर्व अवसर खोलेगा। यह न सिर्फ शुल्क कम करता है, बल्कि सेवाओं और निवेश के लिए नियामक बाधाओं को भी कम करेगा। रल्हन ने कहा, ''एफटीए से भारत के विनिर्माण और सेवा निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा तथा प्रमुख क्षेत्रों में ब्रिटेन से निवेश आकर्षित होगा।'' फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर भारत के उभरते व्यापार ढांचे में मील का पत्थर है, जो गहन वैश्विक आर्थिक एकीकरण के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह घरेलू उद्योगों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जुड़ने और मूल्य शृंखलाओं का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करता है।

एफटीए में डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, सेब शामिल नहीं, 95 प्रतिशत कृषि निर्यात शुल्क-मुक्त

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में डेयरी उत्पादों, खाद्य तेल और सेब को शामिल नहीं किया है, जो घरेलू किसानों के हित में है। इसके साथ ही 95 प्रतिशत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शून्य शुल्क सुनिश्चित किया है। बृहस्पतिवार को हस्ताक्षरित एफटीए में जई पर भी कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है।

दूसरी ओर, हल्दी, काली मिर्च, इलायची जैसी भारतीय खाद्य वस्तुएं; आम का गूदा, अचार और दालें जैसी प्रसंस्कृत वस्तुएं; और झींगा और टूना जैसे समुद्री उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच का लाभ लेंगे। कृषि के क्षेत्र में ब्रिटेन 37.52 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का आयात करता है, जबकि भारत से आयात केवल 81.1 करोड़ डॉलर का ही होता है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ''भारत के किसान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सबसे बड़े लाभार्थी बनने के लिए तैयार हैं, जो उनके उत्पादों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाज़ारों को खोलेगा। इससे उन्हें जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों के निर्यातकों को पहले से मिल रहे लाभ के बराबर या उससे भी फायदा मिलेगा।''

सरकारी निगम-बोर्ड में जैन समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले : प्रवीण बाफना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जीतो कर्नाटक, केरल एवं गोवा जोन के अध्यक्ष प्रवीण बाफना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक सरकार के विधान परिषद सदस्य व कर्नाटक कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष के. अब्दुल जब्बार से शिष्टाचार भेंट की। बाफना ने राजनेता को बताया कि कर्नाटक का जैन समाज राज्य की जरूरतमंद जनता की सेवा में हमेशा ही अग्रणी भूमिका में रहा है। उन्होंने कोरोना काल में जैन समाज द्वारा की गई मानवसेवा कार्य की जानकारी दी। उन्होंने अब्दुल जब्बार से कहा कि आज जैन समाज सरकारी प्रबंधन में शामिल होकर जनता के प्रति अपनी सेवाओं को विस्तार देना चाहता है अतः निगम बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा जैन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की जीतो की मांग सरकार तक पहुंचाएं। प्रतिनिधि मंडल ने सरकारी निगम-बोर्ड में जैन समाज को जोड़ने के साथ कर्नाटक के सभी जिलों में संचालित प्रधानमंत्री 15 सूत्री योजना में सदस्य के रूप सेवा देने का अवसर प्रदान करवाने का भी अनुरोध किया। प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित कर्नाटक अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव व जीतो बेंगलूरु नार्थ के उपाध्यक्ष कमल पुनमिया, जीतो केकेजी जोन के माइनॉरिटी एवं मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ बोहरा, जीतो केकेजी जोन सीएफई संयोजक नितिन कटारिया, जीतो जैन बंधु योजना समिति सदस्य अमित कोठारी एवं समाज सेवी ताराचंद गुगलिया उपस्थित थे। भेंट के दौरान कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के निदेशक मोहम्मद सिराज तथा कर्नाटक अल्पसंख्यक कांग्रेस के एडमिन इरशाद अहमद शेख उपस्थित थे।

भारत तीन प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर रहा : जितेंद्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत तीन प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित कर रहा है, जिनमें से एक रिएक्टर विशेष रूप से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को एक लिखित उत्तर यह जानकारी देते हुए बताया कि ये रिएक्टर मुख्यतः ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव प्लांट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। सिंह ने बताया कि भारत में स्वदेशी रूप से तीन प्रकार के एसएमआर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें 200 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर-200), 55 मेगावाट क्षमता वाला एसएमआर, और पांच मेगावाट थर्मल उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर (जीसीआर) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पांच मेगावाट थर्मल उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर (जीसीआर) को विशेष रूप से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डॉ. सिंह ने कहा कि इन रिएक्टरों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त हो चुकी है, और परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के 60 से 72 महीनों के भीतर इनका निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएसएमआर और एसएमआर के प्रमुख यूनिट्स को परमाणु ऊर्जा विभाग के चयनित स्थानों पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के सहयोग से स्थापित किया जाएगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि इन संयंत्रों के लिए आवश्यक तकनीक देश में उपलब्ध है, और अधिकतर उपकरणों का निर्माण भारतीय उद्योगों की तकनीकी क्षमता के अनुसार, डीएई के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इन रिएक्टरों को कैप्टिव पावर प्लांट्स, सेवानिवृत्त जीवाश्म ईंधन आधारित संयंत्रों के पुनर्प्रयोजन, और परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कार्बन मुक्त ऊर्जा लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सके।

अमरनाथ यात्राः जम्मू आधार शिविर से 3,500 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से बृहस्पतिवार को 3,500 श्रद्धालुओं का नया जत्था दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, 22वें जत्थे में 2,704 पुरुष, 675 महिलाएं, 12 बच्चे और 109 साधु-साध्वियां शामिल हैं। यह जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 140 वाहनों के दो काफिलों में पहलगाम और बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। इनमें से 2,668 श्रद्धालु 95 वाहनों के काफिले में पहलगाम मार्ग के लिए जबकि 45 वाहनों के काफिले में 832 श्रद्धालु बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दो जुलाई को पहले जत्थे को रवाना किए जाने के बाद से अब तक 1,33,878 श्रद्धालु जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। तीन जुलाई से शुरू हुई 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 3.40 लाख से अधिक श्रद्धालु 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष 5.10 लाख श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर में दर्शन किए थे।

न्यायालय का 1984 भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को कम मुआवजा दिया गया, क्योंकि उन्हें अस्थायी विकलांग या मामूली रूप से घायल व्यक्ति के तौर पर गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठनों को इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दे दी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से 2-3 दिसंबर, 1984 की दरम्यानी रात अत्यधिक विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसके बाद 5,479 लोगों की मौत हो गई और पांच लाख से ज्यादा लोग अपंग हो गए। इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। जब मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दशकों बीत चुके हैं। याचिकाकर्ता संगठनों के वकील ने कहा कि उन्होंने याचिका में सीमित अनुरोध किया है और वह किसी मामले को पुनः खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में जांच समिति गठित करने की घोषणा कर सकते हैं बिरलाः सूत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों के आधार की पड़ताल के लिए एक जांच समिति गठित करने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि 21 जुलाई को बिरला को सौंपा गया 152 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस अब ''सदन का दस्तावेज'' है और तीन सदस्यीय समिति के गठन के लिए परामर्श शुरू हो गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। लोकसभा में बीते सोमवार को नोटिस दिया गया था और उसी दिन 63 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक ऐसा ही नोटिस राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा गया था, इसलिए उच्च सदन भी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है।

इस प्रक्रिया के तहत, अध्यक्ष द्वारा प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर दोनों न्यायाधीशों के नाम के लिए उनकी अनुशंसा प्राप्त करने की उम्मीद है, जबकि प्रतिष्ठित न्यायविद का चयन उनका विशेषाधिकार है।

नोटिस सौंपे जाने के बाद से, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श करने में शामिल रहे हैं।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अनुसार, जब किसी प्रस्ताव के नोटिस की सूचना संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्तुत की जाती है, तो न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा एक समिति गठित की जाती है। सोमवार शाम ही एक नाटकीय घटनाक्रम में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।

ब्रिटेन के साथ भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौते की भी जरूरतः कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर से पहले बृहस्पतिवार को कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए ''भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता'' की भी जरूरत है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष किया कि मोदी सरकार की ''भगोड़ानॉमिक्स'' के ये तीन बड़े सितारे अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन बृहस्पतिवार को लंदन में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे श्रम-प्रधान उत्पादों जैसे चमड़ा, जूते और कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात संभव होगा जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा।

यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगा।

जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज लंदन में भारत-ब्रिटेन एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन भारत को ब्रिटेन से एक और भी जरूरी एफटीए करना चाहिए- 'फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट' (भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता)। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, '' आखिरकार, मोदी मॉडल की भगोड़ानॉमिक्स के तीन बड़े स्टार, विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी -अब भी अपनी घर वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं और यह भी संभव है कि इस सूची में कुछ और नाम जल्द जुड़ जाएं।''

कंगना ने अमित शाह से मुलाकात की

हिमाचल में हुई भीषण बारिश और बाढ़ के बारे में जानकारी साझा की

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को हरसंभव सहायता और शीघ्र पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

मंडी से सांसद रनौत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज नई दिल्ली में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर मंडी लोकसभा क्षेत्र में हाल ही में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा की विस्तृत जानकारी साझा की।'' उन्होंने कहा, ''मंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और शीघ्र पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में हिमाचल के साथ मज़बूती से खड़ी है।'' हिमाचल प्रदेश में 22 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से, राज्य भर में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 76 लोगों की मौत हो गई है और 34 लापता हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, इस मानसून में राज्य में 40 बार अचानक बाढ़, 23 बार बादल फटने और 25 बार भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे लगभग 1,247 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

गोवा विस में खूंखार जानवरों के प्रजनन व पालन पर रोक संबंधी विधेयक पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। गोवा विधानसभा ने अदालतों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए दीवानी मुकदमों विशेष रूप से भूमि से संबंधित मुकदमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और खूंखार घोषित किए गए जानवरों के प्रजनन और पालन पर रोक लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुकदमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने संबंधी विधेयक बुधवार को सदन में पारित होने के अवसर पर कहा कि 'गोवा वाद मूल्यांकन विधेयक, 2025' राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न क्षेत्रों में भूमि मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र और शुल्कों से संबंधित विवादों और भ्रम को कम करने के लिए मूल्यांकन में एकरूपता आवश्यक है। मुख्यमंत्री सावंत द्वारा सदन में प्रस्तुत यह विधेयक, मूल्यांकन प्रक्रिया को हाल ही में पारित गोवा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 2024 के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है और यह गोवा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1965 का स्थान लेगा। गोवा विधानसभा ने खूंखार घोषित किए गए जानवरों के प्रजनन और पालतू बनाने पर रोक लगाने संबंधी एक और विधेयक बुधवार को पारित किया जिसमें ऐसे पशुओं के हमलों की स्थिति में मुआवजे और उल्लंघन के आरोप में तीन महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में 'पिटबुल' और 'रॉटवीलर' जैसी खूंखार नस्ल के कुत्तों द्वारा बच्चों को काटने के मामले सामने आने के बाद 'गोवा पशु प्रजनन और पालन (विनियमन और मुआवजा) विधेयक, 2025' पेश किया गया है।

गाजा पर सरकार की चुप्पी निंदनीय, कभी इतनी ''नैतिक कायरता'' नहीं दिखी : कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार गाजा की स्थिति को लेकर चुप है ताकि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाराज न हो जाएं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत सरकार ने कभी इतनी ''नैतिक कायरता'' नहीं दिखायी थी। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''ग़ाजा में फलस्तीनी लोगों पर इजराइली प्रशासन द्वारा भयावह अत्याचार लगातार जारी है। जरूरी खाद्यान्न जैसी मानवीय मदद लेने जा रहे लोगों को बेरहमी से मार दिया जा रहा है या उन्हें जान-बूझकर भूखा रखा जा रहा है। यह सुनियोजित रूप से अंजाम दिया जा रहा एक निर्मम जनसंहार है, जिसमें पूरे समुदाय को मिटाने की कोशिश की जा रही है।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''इसके बावजूद मोदी सरकार पूरी तरह चुप है और प्रधानमंत्री इसलिए पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं ताकि उनके मित्र बेंजामिन नेतन्याहू नाराज न हो जाएं। भारत सरकार ने कभी इतनी नैतिक कायरता नहीं दिखायी।'' रमेश ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय है। उधर, भारत ने गाजा में जारी मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां संघर्षविराम जरूरी है और यह भी स्पष्ट किया कि ''बीच-बीच में संघर्षविराम'' क्षेत्र की जनता के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करने के लिए ''पर्याप्त नहीं'' हैं।

इस साल 21 जुलाई तक विमानों में 183 तकनीकी खामियों की सूचना मिली : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पांच भारतीय एयरलाइन ने इस साल 21 जुलाई तक अपने विमानों में 183 तकनीकी खामियों की सूचना विमानन नियामक डीजीसीए को दी, जिनमें एअर इंडिया समूह के विमानन सेवाओं की 85 खामियां शामिल हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इंडिगो और आकाशा एअर ने क्रमशः 62 और 28 तकनीकी खामियों की सूचना दी, जबकि स्पाइसजेट ने 8 खामियों की सूचना दी। एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कुल मिलाकर 85 तकनीकी खामियों की सूचना दी। ये सभी आंकड़े इस साल 21 जुलाई तक के हैं।

वर्ष 2024 में दर्ज की गईं तकनीकी खामियों की संख्या 421 थी, जो 2023 में रिपोर्ट की गई 448 से कम है। 2022 में रिपोर्ट की गई तकनीकी खामियों की संख्या 528 थी। इन तीन वर्षों के आंकड़ों में एलायंस एअर और पूर्ववर्ती विस्तारा के आंकड़े भी शामिल हैं।

नई दिल्ली में गुरुवार को शाम एआईसीसी के महासचिव और कर्नाटक राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या एवं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार।

सितम्बर में 'क्रांतिकारी' राजनीतिक घटनाक्रम की बात दोहराई : मंत्री राजन्ना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में सितंबर के बाद 'क्रांतिकारी' राजनीतिक घटनाक्रम होने का संकेत दे चुके राज्य के सहकारिता मंत्री एनके राजन्ना ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं। राजन्ना ने 26 जून को जब इस तरह की टिप्पणी की थी, तब साल के अंत तक नेतृत्व में संभावित बदलाव और मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को हवा मिली थी। आज जब राजन्ना से उनकी पिछली टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''यह (क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रम) होने वाला है... मैंने सितंबर की बात कही थी। मैं अब भी उस बयान पर कायम हूं।'' जब राजन्ना से विस्तार से बताने का अनुरोध किया गया, तो उन्होंने कहा, ''अगर मैं अभी सारा खुलासा कर दूंगा, तो कोई जिज्ञासा नहीं बचेगी। जिज्ञासा बनी रहने दीजिए।''

वैसे, मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के समर्थक राजन्ना ने यह भी कहा कि

सिद्दरामय्या पहले ही नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, ऐसे में इस विषय पर कोई भी चर्चा अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा, सिद्दरामय्या ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे, इसलिए यह शर्त भी लागू है। इस पर कोई भी फैसला आलाकमान के स्तर पर लिया जाएगा। सिद्दरामय्या ने जुलाई की शुरुआत में कहा था कि वह मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने दोहराया था कि वह पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे।

राजनीतिक हलकों में खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर इस साल के अंत तक नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलें जोरों पर हैं, जो कथित तौर पर सिद्दरामय्या और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते से जुड़ा है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष पद पर भी बदलाव की चर्चा है, जिस पर शिवकुमार अपने मूल कार्यकाल के बाद भी बने हुए हैं।

राजन्ना ने कहा कि वह अपनी आगामी दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस के कर्नाटक मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''कोई खास कारण नहीं है। वह हमारे प्रभारी महासचिव हैं, इसलिए मैं उनसे मिलकर मामलों पर चर्चा करूंगा।'' जुलाई की शुरुआत में सुरजेवाला की मंत्रियों के साथ एक-एक कर हुई बैठक का 'बहिष्कार' करने की खबरों पर राजन्ना ने स्पष्ट किया, ''मुझे उस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था। अगर मैं शहर में होता, तो उनसे मिलता। लेकिन मैंने निजी कारणों से पहले से ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा तय कर रखी थी, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सका।''

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, अहम स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना और स्थानीय अर्थव्यवस्था उत्प्रेरक कार्यक्रम (एलईएपी) की शुरुआत सहित कई पहलों पर अपनी मुहर लगा दी है। पाटिल ने बताया कि प्रस्तावित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सीओई को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए पांच वर्षों में कुल 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ''सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए-इंडिया) को उद्योग भागीदार के रूप में चुना गया है। इस परियोजना को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 1999 की धारा 4(जी) के तहत छूट दी गई है।'' मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में परीक्षण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से संचालित सुविधाएं वर्तमान में पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और वे अपने खुद के मिशन पर केंद्रित हैं। पाटिल ने कहा कि राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी से हर महीने लगभग 30 कार्यशील प्रोटोटाइप सामने आ रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र परीक्षण की मांग बढ़ रही है। मंत्रिमंडल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था उत्प्रेरक कार्यक्रम (एलईएपी) शुरू करने की भी मंजूरी दे दी, जिसका कुल बजट पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये होगा। पहले वर्ष में कार्यान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

पाटिल के मुताबिक, एलईएपी को कर्नाटक भर में उभरते और मौजूदा स्टार्टअप को समर्थन देने और राज्य को भविष्य के लिए तैयार नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्री ने बताया कि रायचूर में राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के परिसर में 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किदवई पेरिफेरल कैंसर उपचार इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसमें 20 करोड़ रुपये सिविल कार्यों के लिए और 30 करोड़ रुपये उपकरण खरीद के लिए शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने बेंगलूरु स्थित इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान में 450 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर और अन्य उपकरण खरीदने के वास्ते अतिरिक्त 62 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

रेणुकास्वामी मामला : शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को विवेकाधीन शक्ति का अनुचित प्रयोग बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बेंगलूरु। उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और छह अन्य को जमानत प्रदान करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बृहस्पतिवार को विवेकाधीन शक्ति का ''अनुचित प्रयोग'' करार दिया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा अभिनेता और सह-आरोपियों की जमानत मंजूर करने संबंधी 13 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सिद्धार्थ दवे एवं अन्य की दलीलें सुनी। इसने राज्य और कुछ अन्य लोगों द्वारा दाखिल लिखित 'नोट' को रिकॉर्ड में ले लिया और शेष आरोपियों के वकील से एक सप्ताह के भीतर लिखित रूप से संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा।

राहत देने पर सवाल उठाते हुए, ''न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बचाव पक्ष के वकील से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को बरी करने का आदेश दे दिया?'' न्यायाधीश ने कहा, ''चिंता की बात यह है कि जिस तरह से उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश सुनाया...क्या उच्च

न्यायालय हर जमानत याचिका पर एक ही तरह का आदेश सुनाता है?'' पीठ ने दो चश्मदीदों, किरण और पुनीत के बयानों से उच्च न्यायालय के निपटने के तरीके पर भी सवाल उठाया तथा उन्हें ''अविश्वसनीय गवाह'' बताया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, ''यह (जमानत प्रदान करना) आरोपियों को जमानत देने में विवेकाधीन शक्तियों का अनुचित प्रयोग है।'' यह उल्लेख करते हुए कि सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं और मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, अदालत ने पूछा, क्या उच्च न्यायालय ने न्यायिक रूप से अपने विवेक का प्रयोग किया है?''

पीठ ने 17 जुलाई को, उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को जमानत दिए जाने पर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि ''जिस तरह से विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया गया, उससे वह बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है।'' न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो, हम उच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के तरीके से सहमत नहीं हैं।'' न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह मानने की जरूरत है कि इस अदालत के हस्तक्षेप का कोई ठोस कारण नहीं है। लूथरा ने दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत अनुचित थी, खासकर ऐसे मामले में जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत गंभीर आरोप हों।

उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और फोरेंसिक निष्कर्षों सहित प्रमुख साक्ष्यों की उचित जांच किए बिना ही प्रभावी रूप से सुनवाई पूर्व ही ''बरी'' कर दिया। लूथरा ने कहा कि जिस अपार्टमेंट परिसर में कथित तौर पर शव को फेंक दिया गया था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। उन्होंने आरोपों की गंभीरता और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर जोर दिया जो साजिश का संकेत देते हैं। वहीं, दवे ने दलील दी कि जांच में खामियां थीं और देरी से दिए गए बयानों के कारण चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी। दवे ने कहा कि आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय के रवैये पर, खासकर हत्या के आरोपियों से गंभीरता से निपटने के तरीके पर, चिंता व्यक्त की।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, ''हम उच्च न्यायालय द्वारा की गई गलती को नहीं दोहराएंगे। हम यहां दोषी या निर्दोष होने का फैसला करने नहीं, बल्कि यह पड़ताल करेंगे कि जमानत सही तरीके से दी गई थी या नहीं।'' पीठ राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

नाबालिग की सगाई को अपराध बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए बृहस्पतिवार को बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जिसमें नाबालिगों की सगाई को भी दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और विधेयक विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि 2023-24 के दौरान राज्य में लगभग 700 बाल विवाह की सूचना मिली थी। यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसमें जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे।

केनरा बैंक का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत बढ़कर 4,752 करोड़ रुपये

बेंगलूरु/नई दिल्ली/दक्षिण भारत । सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत बढ़कर 4,752 करोड़ रुपये हो गया। बेंगलूरु स्थित इस बैंक का गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में मुनाफा 3,905 करोड़ रुपये रहा था।

केनरा बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी कुल आय बढ़कर 38,063 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 34,020 करोड़ रुपये थी। बैंक द्वारा अर्जित ब्याज इस दौरान बढ़कर 31,003 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 28,701 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन तिमाही में बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर 8,554 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 7,616 करोड़ रुपये था।

बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया। सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) अप्रैल-जून तिमाही के अंत में सकल अग्रिमों के 2.69 प्रतिशत पर आ गईं, जो एक साल पहले 4.14 प्रतिशत थीं। इसी प्रकार, शुद्ध एनपीए या डूबा ऋण घटकर 0.63 प्रतिशत रह गया जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.24 प्रतिशत था।

महादयी परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी कर्नाटक के लोगों का अपमान है : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने गोवा के अपने समकक्ष प्रमोद सावंत पर राज्य के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कहा, 'महादयी परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी कर्नाटक के लोगों का अपमान है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई चिंता क्यों नहीं जताई?'

सिद्दरामय्या ने कहा, 'क्या भाजपा के शासन में संघवाद इसी तरह काम करता है? पीठ पीछे ध्वंस, चुप्पी और विश्वासघात? कन्नड़ लोगों ने क्या गुनाह किया है? क्या हमें भाजपा के आगे

आत्मसमर्पण न करने की सज़ा मिल रही है?'

सिद्दरामय्या ने कहा, 'महादयी लग्जरी या बर्बादी के लिए नहीं है, यह उत्तरी कर्नाटक की पेयजल जरूरत के लिए है। दशकों से, हमारे लोग इन्साफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में भाजपा और जनता दल (एस) के नेताओं में बोलने की हिम्मत नहीं है। उनकी आज की खामोशी कल याद रखी जाएगी।'

सिद्दरामय्या ने कहा, 'वर्ष 2018 के ट्रिब्यूनल के फैसले में, हमें 13.42 टीएमसी पानी आवंटित किए जाने के बावजूद, केंद्र, गोवा की भाजपा सरकार के साथ मिलकर, हमारी उचित परियोजना के कार्यान्वयन को रोक रहा है।' सिद्दरामय्या ने कहा, 'यह परियोजना बेलगावी, धारवाड़, गदग, बागलकोट और आस-पास के क्षेत्रों के 40 लाख से ज़्यादा लोगों की प्यास बुझाएगी। यह एक जीवन रेखा है, कोई सौदेबाज़ी की चीज़ नहीं है।' सिद्दरामय्या ने कहा, 'हम कानूनी, राजनीतिक और नैतिक रूप से तब तक लड़ेंगे, जब तक कर्नाटक को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल जाता।'

आरसीबी भगदड़ में जान गंवाने वाली की मां का आरोप

'पोस्टमार्टम के दौरान कान की बालियां चोरी हो गईं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) के आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास चार जून को मची भगदड़ में जान गंवाने वाली 14 वर्षीय लड़की की मां ने पुलिस ने आरोप लगाया गया है कि पोस्टमार्टम के दौरान उसकी बेटी की सोने की बालियां एवं अन्य सामानों की चोरी हो गयी। जान गंवाने वाली लड़की दिव्यांशी की मां अश्विनी ने इस सिलसिले में बृहस्पतिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

अश्विनी ने संवाददाताओं से कहा कि परिवार द्वारा उपहार में दी गईं कान की बालियां दिव्यांशी के लिए भावनात्मक रूप से बहुत अहम थीं तथा अंत्यपरीक्षण के बाद जब दिव्यांशी का शव लौटाया गया, तब ये बालियां गायब थीं। उन्होंने बताया, ''दिव्यांशी ने एक साल से उन बालियों को नहीं उतारा था। परिवार ने ये बालियां उपहार के तौर पर दी थीं तथा उसका गहरा भावनात्मक मोल था। हम उन्हें याद के तौर पर संभालकर रखना चाहते थे।'' अश्विनी का दावा है कि उन्होंने अस्पताल के डीन समेत कई अधिकारियों और थानों से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, चोरी की बात सबने मानी, पर बालियां वापस नहीं दी गयीं। यह सिर्फ बालियों की कीमत की बात नहीं है। वे हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चार जून को आरसीबी के जुलूस में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे।

अरुणाचल के मंत्री ने बेंगलूरु में आईआईटीएम ट्रैवल फेयर का उद्घाटन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (आईआईटीएम) ने गुरुवार को त्रिपुरा वासिनी पैलेस ग्राउंड में आधिकारिक तौर पर अपने द्वार खोल दिए, जो यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और गंतव्य विपणन के क्षेत्र में बेहतरीन तीन दिवसीय प्रदर्शन का आगाज था। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पासाग दोरजी सोना ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने पर ज़ोर दे रही है। उन्होंने कहा, शांति और पर्यटन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यटन इस भूमि की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम है। जहाँ सभी राज्य ऐसा कर रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश आराम से नहीं रह सकता। इस तरह के आयोजन हमें अपने पंख फैलाने और अधिक उत्साही लोगों तक पहुँचने का अवसर प्रदान करते हैं।

कर्नाटक के पर्यटन विभाग के निदेशक डॉ. आर राजेंद्र, आईएएस, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्यामाराजू, जंगल लॉजेस एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रशांत शंखिनामठ, आईएफएस, छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग के चेयरमैन नीलू शर्मा, निदेशक विवेक आचार्य आदि अन्य उपस्थित थे। आईआईटीएम भारत की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी है जो यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य, अवकाश और अन्य संबंधित उद्योगों को एक छत के नीचे लाती है। इसका उद्देश्य उद्योग को यात्रा उद्योग, कॉर्पोरेट खरीदारों और अंतिम ग्राहकों के साथ आमने-सामने लाना है। इस आयोजन में ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर, डीएमसी, होटल और रिसॉर्ट, राष्ट्रीय पर्यटन कार्यालय, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल आदि भाग लेंगे। इस वर्ष आईआईटीएम अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह पर्यटन मेला 26 जुलाई को समाप्त होगा। आईआईटीएम में 25 भारतीय राज्यों और 20 अंतर्राष्ट्रीय स्थलों से 800 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं, जो तीर्थयात्रा, रोमांच, संस्कृति, वन्य जीवन आदि जैसे विविध यात्रा विकल्पों का प्रदर्शन करते हैं।

मंत्रिमंडल ने स्टेडियम में मची भगदड़ पर न्यायमूर्ति डी कुन्हा की रिपोर्ट स्वीकार की

बेंगलूरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के निकट हुई भगदड़ की घटना पर न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा की रिपोर्ट को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया। स्टेडियम में चार जून को हुयी भगदड़ की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गये थे।

उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई निजी संघों, आरसीबी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स जैसी कंपनियों के खिलाफ की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, विभागीय जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भगदड़ और लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनका नाम न्यायमूर्ति डी कुन्हा की रिपोर्ट में दर्ज है। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने इस हादसे के एक दिन बाद पांच जून को न्यायिक जांच का आदेश दिया था।

गोवा के मुख्यमंत्री 'मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', कर्नाटक महादयी नदी परियोजना पर आगे बढ़ेगा : डीके शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने महादयी नदी परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और राज्य इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा। जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने कहा कि यह कार्य कर्नाटक की भूमि पर किया जा रहा है और उन्होंने इसे आगे बढ़ाने की सरकार की मंशा की पुष्टि की। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री को अंतरराज्यीय संबंधों के महत्व की भी याद दिलाई और कहा कि वह इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। गोवा विधानसभा में मंगलवार को सावंत ने दावा किया था कि महादेई परियोजना को केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा सरकार महादेई नदी के पानी को मोड़ने के उद्देश्य से की जा रही गतिविधियों के लिए कर्नाटक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करेगी।

शिवकुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया, ''गोवा के मुख्यमंत्री ने महादेई जल मुद्दे पर बात की है। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं; उन्हें संघीय ढांचे की जानकारी नहीं है। महादयी जल आवंटन पर पहले ही फैसला हो चुका है और निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।''

उन्होंने कहा, ''निविदा जारी कर दी गई है और काम शुरू होना है। केवल वन मंजूरी की आवश्यकता है और हमें नोटिस भी दिया गया है - लेकिन कहीं भी हमें यह नहीं बताया गया कि काम शुरू न करें।'' शिवकुमार ने कहा, ''उनका (गोवा के मुख्यमंत्री का) बयान निंदनीय है। वह हमें रोक नहीं सकते; उनके पास यह अधिकार नहीं है। मैं काम शुरू करूंगा। उन्हें इसे रोकने की कोशिश करने दीजिए -मैं भी तो जरा देखूं।''

न्यायालय ने रूसी महिला के बच्चों के निर्वासन पर रोक लगाई

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक रूसी महिला के बच्चों के निर्वासन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है। अदालत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के अनुसार बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव का यह निर्णय एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो बच्चों के खिलाफ जारी अचानक निर्वासन आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि निर्वासन प्रक्रिया में बच्चों के कल्याण की अनदेखी की गई तथा यूएनसीआरसी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बीना पिल्लई ने किया। भारत सरकार की ओर से इस मामले में पेश हुए सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को बताया कि बच्चों के पास वर्तमान में वैध यात्रा या पहचान दस्तावेज नहीं हैं। इस दलील के आधार पर, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर तत्काल निर्वासन उचित नहीं है। नीना कुटीना (40) को उनकी दो बेटियों प्रिया (6) और अमा (4) के साथ 11 जुलाई को उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण में रामतीर्थ गुफा से पुलिस ने बचाया था। कुटीना वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद यहां रह रही थी।

मोदी सरकार ने कर्नाटक मॉडल की सफलता को स्वीकार किया : कांग्रेस

नई दिल्ली/बेंगलूरु। कांग्रेस ने संसद में सरकार द्वारा दिए गए एक सवाल के जवाब का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मोदी सरकार ने 'कर्नाटक मॉडल' की अद्वितीय सफलता को स्वीकार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 21 जुलाई को लोकसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद गिरिधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के उत्तर की एक प्रति 'एक्स' पर साझा की। उन्होंने कहा, ''21 जुलाई, 2025 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, मोदी सरकार ने कर्नाटक मॉडल की अद्वितीय सफलता को स्वीकार किया। कर्नाटक का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) देश में सबसे अधिक है। 2,04,605 रुपये के साथ कर्नाटक का एनएसडीपी, 1,14,710 रुपये की शुद्ध राष्ट्रीय आय से 78 प्रतिशत अधिक था।'' रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले निवेश और सामाजिक कल्याण के संयोजन का बीड़ा उठाया है और अब यह वह मॉडल है जिसका देश को अनुसरण करना चाहिए।

देवनानी ने सिंदूर का पौधा लगाकर कारगिल शौर्य वाटिका में पौधारोपण का किया शुभारम्भ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी पहल पर ही विधानसभा में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका में गुरुवार को सिंदूर का पौधा लगाकर पौधारोपण का शुभारंभ किया।

देवनानी ने विधानसभा में तैयार की गई कारगिल शौर्य वाटिका में हरियाली अमावस्या पर एक दिन में पांच प्रजातियों के 1100 पौधे लगाने की सिंदूर का पौधा लगाकर शुरुआत की। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर देवनानी के साथ वीरांगनाओं ने भी विधानसभा की कारगिल शौर्य वाटिका में पौधे लगाये। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर तथा कई विधायकों ने भी वाटिका में पौधारोपण किया।

देवनानी ने बताया कि विधानसभा परिसर में कारगिल विजय में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि इस वाटिका में सिंदूर, एरिका पाम, सांग ऑफ इण्डिया, किसना फाइकस और क्रोटोन प्रजाति के पौधे लगाये गये हैं। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने वाले यह पौधे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाने वाले इन पौधों की पत्तियों का उपयोग पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली में उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध जो 1999 में कारगिल सेक्टर में लड़ा गया था, वह भारतीय सेना के साहस और बलिदान का महत्वपूर्ण उदाहरण है। शौर्य वाटिका इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरता को समर्पित है।

'राजस्थान विश्वविद्यालय' के विद्यार्थियों के एक समूह ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक समूह ने बृहस्पतिवार को यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर राज्य में छात्र संघ चुनावों में हो रही देरी पर चिंता जताई। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार (2003-2008) के कार्यकाल के दौरान स्थगित कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 2010 में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू कर दिए गए थे। गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में चुनाव एक बार फिर रोक दिए गए थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2022 में प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 2023 में छात्र संघ चुनाव फिर से स्थगित कर दिए गए क्योंकि विधानसभा चुनावों और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए कॉलेजों को अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर लिया गया था। हालांकि दिसंबर 2023 में राज्य में भाजपा सरकार आई और उसने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी छात्र संघ चुनाव बहाल करने का मुद्दा उठाया है।

अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे लाभ और वास्तविक जरूरतमंद सशक्त हो : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बालोतरा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने वंचितों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर देते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस प्रकार हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे और वास्तविक जरूरतमंद वर्ग सशक्त हो सके। बागड़े गुरुवार को बालोतरा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए।

उन्होने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

इस दौरान राज्यपाल ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से देने को कहा। बैठक के दौरान बागड़े ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, कुसुम योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, राजीविका, डेयरी विकास एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आवास योजना एवं अन्य योजनाओं में प्राथमिकता के साथ लाभान्वित किया जाए।शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को एक साथ विकसित किया जाए। उन्होंने जिले के स्कूलों में खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और छात्रावासों में व्यायामशाला एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिशन हरियालो राजस्थान को और अधिक प्रभावी बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहा जाए बल्कि उनकी सुरक्षा और सार-संभाल भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कम जल आवश्यकता वाले पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने को कहा ताकि पर्यावरणीय संतुलन के साथ जल संरक्षण भी संभव हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की समीक्षा करते हुए जल संचयन एवं भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में स्थानीय समाधान अपनाने पर बल दिया। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (राजीविका) के तहत महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए और प्रत्येक महिला को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए।

निष्क्रिय समूहों को पुनः सक्रिय करने और स्थानीय उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने अंत में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य नागरिक को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि धरातल पर नजर आनी चाहिए।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कुमावत ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह से भेंट कर उन्हें राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन 'प्रगति पुस्तिका' के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की एवं संबंधित मांगें उनके समक्ष प्रस्तुत की।

इसी क्रम में कुमावत ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर कुमावत ने उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करती पुस्तिका भी केंद्रीय मंत्री को भेंट की। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने नई दिल्ली में पाली लोकसभा से सांसद एवं 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (गझउ) के चेयरमैन पी. पी. चौधरी से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पाली लोकसभा सहित राजस्थान से जुड़े विभिन्न जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा की।

मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेले का अवलोकन किया। इस दौरान कुमावत ने कहा कि राजस्थानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेले मिल का पत्थर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की देश-विदेश में लगातार मांग बढ़ रही है और राज्य सरकार भी उन्हें बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध है। कुमावत ने मेले में लगे स्टालों पर व्यक्तिश जाकर राजीविका और रूडा के विक्रेता कारीगरों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके उत्पादों की सराहना की। पत्रकारों से बात करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा की राजधानी में राजस्थान की सरस डेयरी के दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है तथा बीकानेर हाउस में सरस पार्लर खोलने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

पिता ने डेढ़ वर्षीय बेटे को बोरवेल में फेंका

जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में एक पिता ने अपने डेढ़ वर्षीय बेटे को बोरवेल में कथित तौर पर फेंक दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जमवारामगढ़ के दीपोला गांव में हुई इस घटना में बच्चे को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार रात की है और स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया।

जमवारामगढ़ के थानाधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि आरोपी ललित अपने बेटे की बीमारी और पत्नी के लंबे समय तक मायके में रहने जैसे कारणों से परेशान था। शर्मा ने बताया कि ललित कल (बुधवार को) एक चिकित्सक के पास गया और अपने बेटे के लिए दवाइयां लीं। उन्होंने बताया, आरोपी ने दावा किया कि उसके बेटे की कल (बुधवार को) रात मौत हो गई और इसके बाद उसने उसे एक सफेद कपड़े में लपेटकर बोरवेल में फेंक दिया। उसने अपने भाई को इस बारे में बताया। जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो पुलिस को सूचित किया गया। राज्य आपदा मोचन बल की एक टीम बचाव अभियान में जुटी है। अधिकारी ने बताया, ललित को हिरासत में ले लिया गया ।

धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारणों का खुलासा करे केंद्र सरकार : सचिन पायलट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे दिए जाने पर बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार को इस घटनाक्रम के कारणों का खुलासा करना चाहिए। पायलट ने टोंक में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, इस तरह से अचानक इस्तीफा दिये जाने से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार को न तो संविधान की, न संवैधानिक संस्थाओं की और न ही संवैधानिक पदों की कोई परवाह है। उन्होंने कहा, आज नहीं तो कल इसका खुलासा जरूर होगा। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से (जगदीप) धनखड़ साबब ने इस्तीफा दिया होगा। जरूर कुछ न कुछ दबाव होगा, कुछ न कुछ कहा सुना गया होगा।

पायलट ने कहा, जल्दबाजी में पर्दे के पीछे चुपचाप तरीके से इस्तीफे लिए जा रहे है, लोगों को हटाया जा रहा है... इन कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज नहीं कल पूरी बात सामने आएगी और कारण पता चलेंगे। जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। पायलट ने कहा, उनका (धनखड़) का व्यक्तिगत निर्णय है लेकिन कुछ मसला जरूर है। क्योंकि उपराष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति के बाद नंबर दो का संवैधानिक पद है। भाजपा व केंद्र सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का कभी मान सम्मान किया नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा, बिना वजह कुछ नहीं होता है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां थीं जहां पर किसान पृष्ठभूमि वाले एक व्यक्ति को अचानक अपना पद छोड़ना पड़ा।? पायलट ने कहा, जो लोग युवाओं की बात करते हैं, उन्हें उनके लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास इसके लिए समय नहीं है क्योंकि वह विदेश यात्राओं में बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और कोई शासन-प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। पायलट ने आरोप लगाया, असली मुद्दा यह है कि सरकार का कानून-व्यवस्था पर कोई नियंत्रण रहा नहीं है। रोजगार और विकास के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

डिजिटल हेल्थ कोर्सेज से स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा सुधार : गजेन्द्र सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मुख्य आतिथ्य में गुरूवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस), जयपुर और कोइटा फाउंडेशन, मुम्बई के बीच डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स (डीएचएफसी) प्रारंभ करने हेतु एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एमओयू पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार हरफूल पंकज एवं कोईटा फाउण्डेशन की ओर से कोफाउण्डर एवं निदेशक रिजवान कोईटा ने हस्ताक्षर किए। यह एमओयू चिकित्सा अध्ययन से संबंधित विद्यार्थियों और स्वास्थ्यकर्मियों को डिजिटल टूल्स की जानकारी और उनके प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि देशदुनिया में डिजिटल हेल्थ का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। राजस्थान सरकार भी चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीक एवं डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। चिकित्सा विभाग ने राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन लागू किया गया है। इसके तहत समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में ऑनलाइन किया जा रहा है। आमजन के हेल्थ रेकार्ड को डिजिटली संधारित करने एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए आभा आईडी बनाई जा रही है। अब तक 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।

खींवसर ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का एक बड़ा आधारभूत ढांचा स्थापित है। इसे बेहतर तरीके से संचालित करने तथा रोगियों को सुविधापूर्वक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटलाइजेशन का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 12 हजार स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बदला गया है, जिन्हें तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कम्प्यूटर, लैपटॉप, एलईडी सहित अन्य तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। साथ ही, यहां टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि गांवढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित हो। आज हुए एमओयू से प्रदेश के युवा डिजिटल हेल्थ कोर्स का लाभ ले सकेंगे। इससे अस्पतालों में कार्य क्षमता में वृद्धि होगी एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आ सकेगा।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में डिजिटल हेल्थ कोर्स महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे हेल्थ रेकार्ड का डिजिटली संधारण होने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशिल इंटेलीजेंस को बढ़ावा मिलेगा। अस्पतालों एवं जांच लैब आदि में प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का उपयोग विगत वर्षों में तेजी से बढ़ा है।

कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रहे : महाजन

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारियों को लेकर गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त व सभी 5 जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सिरोही जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अधीनस्थ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूचियों का शोधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए। महाजन ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक हेल्प डेस्क स्थापित कर सुनिश्चित किया जाए कि इन हेल्प डेस्क पर नियुक्त व्यक्ति एसआईआर कार्यक्रम और उसके दिशा-निर्देशों से पूरी तरह से अवगत हों।

महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अभियान का मूल उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि रैंडम चेकिंग के लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली से संबंधित ऑनलाइन माध्यमों को युवाओं के मध्य अधिक लोकप्रिय बनाना है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना साकार होगी।

राजस्थान 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में पहले पायदान पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहले पायदान पर पहुंच गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचित किए गए प्रावधानों से अब तक पूरे देश में प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक आवंटित हुए हैं, इनमें से राजस्थान में ही देश के 20 प्रतिशत से अधिक यानी 103 ब्लॉक आवंटित हुए है वहीं राज्य सरकार के गत 18 महीनों के अल्प कार्यकाल में ही 64 ब्लॉकों का ऑक्शन हो चुका है।

इस उपलब्धि के बाद राज्य सरकार सभी ब्लॉक्स के शीघ्र परिचालन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश में निवेश और राजस्व की वृद्धि अधिक से अधिक हो सके। राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। शर्मा की मंशानुसार खान विभाग ने एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन, ब्लॉक निर्माण और पारदर्शी ऑक्शन की प्रभावी योजना पर कार्य किया है।

जिसके तहत मिनरल ब्लॉक्स के निस्तारण के संबंध में त्वरित निर्णय लिए जा रहे है। सरकार के गठन के तीन महीनों के भीतर ही (मार्च 2024 तक) 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से कर दी गई वहीं वर्ष 2024-25 में अकेले 34 ब्लॉकों की नीलामी कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया गया। खान विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में जुलाई तक 15 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है और 12 ब्लॉकों की प्रक्रिया जारी है वहीं खान विभाग ने रॉयल्टी राजस्व में एक नया रिकॉर्ड बनाया।

खान विभाग ने जुलाई में राजस्व, वन एवं पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो और स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (सिया) सहित संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर लाकर खनिज ब्लॉकों और प्लॉटों के परिचालन को गति देने की अभिनव पहल की है।

सांगरिया सैटलाइट अस्पताल से क्षेत्रवासियों को मिलेगी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं : पटेल

जयपुर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान - हरियाळो-राजस्थान के तहत जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत सांगरिया पंचायत समिति लूणी में वृक्षारोपण कार्यक्रम गुरुवार को संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने तेजाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर संसदीय कार्य ने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान की शुरुआत की और पिछले वर्ष लगभग साढ़े सात करोड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा हरियाली तीज के दिन प्रदेश भर में ढाई करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से बारिश के इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और हरियालो राजस्थान के संकल्प साकार करने का आह्वान किया।

पटेल ने कहा यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित ऐतिहासिक बजट दिया है। उन्होंने कहा सांगरिया सैटलाइट अस्पताल से क्षेत्रवासियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी।

महानदी विवाद को बातचीत से सुलझाने के

पटनायक ने ओडिशा सरकार के कदम पर सवाल उठाए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान किए जाने के पक्ष में बयान देने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार (इस मामले में) कानूनी रास्ते से पीछे हट गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद माझी ने कहा कि चूंकि केंद्रीय जल आयोग में समस्या को हल करने के प्रयास धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों राज्यों के बीच बातचीत के जरिए इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पटनायक ने कहा, लोगों को जवाब मिलना चाहिए। कल, माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद पर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और महाधिवक्ता की एक पोस्ट के अनुसार, इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महानदी जल न्यायाधिकरण का गठन हुआ था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इससे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस की नई पीढ़ी के संस्कार देश देख रहा है : बिरला

नारेबाजी और तख्तियां लाना कांग्रेस के संस्कार नहीं रहे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

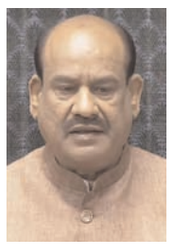

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में हंगामा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों को आड़े-हाथों लिया और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के संस्कार सदन में नारेबाजी करने, तख्तियां लाने और मेजें ठोंकने के लिए नहीं रहे हैं, लेकिन इस दल के मौजूदा सांसदों का आचरण पूरा देश देख रहा है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विषय पर हंगामा किया जिससे कार्यवाही बाधित हुई। बिरला ने कहा, '' आपसे पहले भी कहा गया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें जनता के महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और सरकार की जवाबदेही होती है...कई सांसदों ने कहा कि उनका प्रश्नकाल के दौरान मुश्किल से प्रश्न आता है, लेकिन आप लोगों का जिस तरह का व्यवहार होता है, वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है।'' उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, ''आप लोग इतने पुराने राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, जिसका इस सदन के अंदर गरिमा और मर्यादा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन लोग देखेंगे कि आप किस तरह से सदन में व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं और मेजें ठोकते हैं।'' लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों का आह्वान किया कि वे संसद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखें। उनका कहना था, ''यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता और जवाबदेही को दुनिया जानती है। आप इस तरह का आचरण करेंगे तो इसका लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्या संदेश जाएगा।'' बिरला ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से कहा, 'वेणुगोपाल जी, क्या आप अपने सांसदों को यही सिखाते हो। नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, मेज थपथपाना आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी जिस तरह का संस्कार पेश कर रही है वो पूरा देश देख रहा है।'' उन्होंने कहा, ''आप लोग माननीय हैं, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है...तख्तियां लेकर मेजें तोड़ने के लिए नहीं भेजा है।'' बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि संसद पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा का अवसर दिया जाएगा।

भागवत ने मौलानाओं के साथ किया मंथन, इमामों और पुजारियों के बीच संवाद पर सहमति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को इमामों और मुस्लिम विद्वानों के साथ बैठक की जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संवाद जारी रखने पर सहमति जताई गई।

'ऑल इंडिया इमाम आर्गनाइज़ेशन' के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी की तरफ से इस बैठक का आयोजन यहां हरियाणा भवन में किया गया था, जिसमें भागवत के अलावा संघ के कुछ अन्य पदाधिकारी और 60 इमाम, मुफ्ती एवं मदरसों के मोहतमिम (कुलपति) मौजूद थे।

इलियासी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यह बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली और इसमें मुसलमानों से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई और यह सहमति बनी कि संवाद का यह सिलसिला बरकरार रहेगा। आरएसएस ने बैठक को ''सकारात्मक'' बताया और कहा कि यह समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक संवाद की ''निरंतर प्रक्रिया'' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह है कि देश के हित में सभी लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। संघ के राष्ट्रीय प्रचार एवं मीडिया विभाग के प्रमुख सुनील आंबेकर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''यह समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक संवाद की एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश हित में सभी लोग मिलकर कैसे काम कर सकें। आज की चर्चा भी सकारात्मक रही।''

बैठक में आरएसएस की तरफ से भागवत के साथ कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इलियासी ने कहा, ''बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि मंदिरों और मस्जिदों, इमामों और पुजारियों, गुरुकुलों और 'मदरसों' के बीच संवाद होना चाहिए।'' उनके मुताबिक, आरएसएस प्रमुख ने इस विचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बात पर आम सहमति बनी कि उनका संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे।

ममता ने बंगालियों के खिलाफ 'भाषाई आतंक' का आरोप लगाया

भाजपा शासित सरकारों की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य के बांग्ला भाषी गरीब श्रमिकों को भाजपा शासित कुछ राज्यों के अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और यहां तक कि बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उन्होंने इन घटनाओं को ''भाषाई आतंक'' करार दिया।

बनर्जी ने 'एक्स' पर कड़े शब्दों में लिखी गई एक पोस्ट में हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर बांग्ला भाषी नागरिकों पर ''अत्याचार और यातनाएं'' देने का आरोप लगाया और सवाल किया कि भाजपा ऐसी कथित कार्रवाइयों के जरिए क्या साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से हमारे बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की लगातार रिपोर्ट मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस को हरियाणा पुलिस से पहचान की पुष्टि के अनुरोध के नाम पर ये रिपोर्ट मिल रही हैं।'' तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि उन्हें राजस्थान जैसे राज्यों से उचित दस्तावेज होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के नागरिकों को अवैध तरीके से सीधे बांग्लादेश भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। बनर्जी ने आरोप लगाया, ''इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के असहाय गरीब बंगाली कामगारों पर अत्याचार हो रहा है। मैं भारत में बंगालियों पर 'डबल इंजन' वाली सरकारों के इन भयानक अत्याचारों को देखकर स्तब्ध हूं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? यह नृशंस और भयावह है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भाषाई आतंक को रोकें।''

बिहार में अगर सफल हुआ तो सभी चुनावी राज्यों में लागू किया जाएगा एसआईआर : माणिक सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अगरतला/भाषा। वरिष्ठ वामपंथी नेता माणिक सरकार ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि यदि निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में सफल होता है, तो इसी तरह की कवायद पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में भी हो सकती है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता सरकार ने यहां आयोजित पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अचानक शुरू की गई, जबकि स्थापित परंपरा के अनुसार मतदाता सूची का नियमित संशोधन जनवरी 2024 में पूरा हो जाना था। उन्होंने कहा, ''एसआईआर का उद्देश्य उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना है जो भारतीय नहीं हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रक्रिया में उसकी भूमिका संविधान की भावना के विरुद्ध है।'' माणिक सरकार ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में 52 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं जिनमें अधिकतर अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) और महिलाएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा जानती है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में उसकी स्थिति कमजोर है। उसे पता है कि इन समुदायों के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे।

मृत, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं रह सकते : सीईसी

नई दिल्ली/भाषा। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग किसी प्रभाव में आकर मृतकों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों या कई जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दे सकता। उनकी यह टिप्पणी विपक्षी दलों द्वारा बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोग पर बढ़ते हमलों के बीच आई है। विपक्ष का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

आयोग के अनुसार, उन्होंने कहा, ''क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं है?'' उन्होंने कहा कि पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अपात्र लोगों को वोट देने की अनुमति देना संविधान के विरुद्ध है। बिहार में मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर जांच करने पर निर्वाचन अधिकारियों ने अब तक पाया है कि 52 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर मौजूद नहीं थे और 18 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। आयोग ने बताया है कि एसआईआर के निर्देशों के अनुसार, किसी भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा ताकि वे निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा छोड़ दिए गए किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करवा सकें या बीएलओ/बीएलए द्वारा गलत तरीके से शामिल किए गए किसी मतदाता का नाम हटवा सकें।

मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक बजट की तरह

भारत को फिर से प्रभावशाली आर्थिक सुधारों की जरूरत: खरगे

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक बजट का हवाला देते हुए कहा कि भारत को वर्तमान समय में भी उसी तरह के प्रभावशाली आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन पिछले 11 वर्षों में सरकार की नीतियों में जड़ता की स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की ''विनाशकारी आर्थिक नीतियों'' के कारण अर्थव्यवस्था कम विकास दर से जूझ रही है। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 24 जुलाई, 1991 को वह बजट पेश किया था जिसने भारत में उदारीकरण की बजबूत बुनियाद रखी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ''असमानता बढ़ी है, वेतन वृद्धि बुरी तरह से स्थिर हो गई है, घरेलू बचत कम हो रही है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, मध्यम वर्ग और गरीबों को 'करीबी दोस्तों' की मदद के लिए लूटा जा रहा है और हम एक व्यापार युद्ध का सामना कर रहे हैं, जो हमारे कृषि और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा।'' उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियों में दूरदर्शिता का अभाव है। खरगे ने कहा कि 1991 का बजट भारत के लिए एक ''महत्वपूर्ण क्षण'' था, जब देश और उसके नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। उन्होंने कहा, ''तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में भारत ने आर्थिक सुधारों के सिलसिले के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मध्यम वर्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।''

असम में अवैध कब्जे को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच नगालैंड में हाई अलर्ट

कोहिमा/भाषा। असम में कथित अवैध अप्रवासियों को निशाना बनाकर अवैध कब्जे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच नगालैंड सरकार ने परामर्श जारी किया है तथा राज्य में विस्थापित लोगों के संभावित आगमन को रोकने के लिए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। नगालैंड के आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में सभी उपायुक्तों को राज्य की जनसांख्यिकीय अखंडता की रक्षा करने, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बनाए रखने, सक्रिय उपाय लागू करने व सीमावर्ती क्षेत्रों और पारगमन बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

नगालैंड और असम की लगभग 512 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा है। यह सीमा दोनों ओर के कई जिलों को जोड़ती है। न्यूलैंड जिले के अधिकारियों ने असम से निकाले व्यक्तियों को ले जाने के संदेह में 200 से अधिक वाहनों को वापस लौटाने की सूचना दी। घरेलू सामान ले जा रहे इन ट्रकों को कई जांच चौकियों पर रोका गया और स्थानीय अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवी समूहों ने उनमें सवार लोगों से पूछताछ की।

चुनाव बहिष्कार संबंधी तेजस्वी के बयान पर कांग्रेस ने कहा : सारे विकल्प खुले हुए हैं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार से संबंधित बयान को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की ''तुगलकी प्रक्रिया'' को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी विकल्प खुले हुए हैं।

पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने यह भी कहा कि 'इंडिया' गठबंधन की ओर से सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर उनकी पार्टी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का ''विकल्प खुला'' है।

तेजस्वी यादव के बयान के बारे में कांग्रेस का पक्ष पूछे जाने पर अल्लावरु ने संवाददाताओं से कहा, ''सारे विकल्प खुले हुए हैं।'' उन्होंने कहा, ''चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है कि जितने भी आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सरासर गलत हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 24 जून को जो प्रक्रिया अपने आदेश में लिखी है, उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग जो भी आंकड़े अपनी वेबसाइट या कहीं और दिखा रहा है, वो सरासर झूठे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ''बिहार की जनता की तरफ से हम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक-एक हज़ार लोगों को चुना जाए और उनसे बात करके यह देखा जाए कि प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि नहीं।''

उन्होंने दावा किया, ''अगर आंकड़े 25 प्रतिशत भी सही निकल के आ जाते हैं तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, वो लोगों के पास हैं नहीं।''

गुरुजी यह जंग भी जीतेंगे : हेमंत सोरेन

रांची/भाषा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन अपने स्वास्थ्य की जंग भी जीतेंगे, जिस प्रकार उन्होंने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं। शिबू सोरेन पिछले एक महीने से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने अस्पताल पहुंच कर उनका हालचाल लिया है। सोरेन की बीमारी के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य ज्यादातर दिल्ली में ही रह रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता के बाद मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है... गुरुजी ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और यह जंग भी वह जरूर जीतेंगे।

मिथुन ने ममता के बंगाली प्रवासियों को परेशान करने के दावे का खंडन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और अन्य राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के संबंध में उनके हालिया बयान को निराधार करार देते हुए उन पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए भय फैलाने का आरोप लगाया। चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेतृत्व निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से घबरा गया है, क्योंकि उन्हें अपने अवैध वोट बैंक से नियंत्रण गंवाने का डर है। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस के नेता जानते हैं कि एक बार घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए तो वे 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 70 भी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए वे घबरा रहे हैं और निर्वाचन आयोग के पुनरीक्षण अभियान का विरोध कर रहे हैं।

चक्रवर्ती ने कहा कि बनर्जी की टिप्पणी का उद्देश्य बंगाल के लोगों में विवाद पैदा करना और अनावश्यक दहशत पैदा करना है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य चक्रवर्ती ने कहा, वह हर चीज़ में विवाद पैदा करना चाहती हैं। कुछ नहीं होने वाला है। बांग्ला भाषा जैसी है वैसी ही रहेगी।

ओडिशा: भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी अधिकारी गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सतर्कता विभाग ने भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के एक कार्यकारी अभियंता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार को की गई छापेमारी में अभियंता के नाम पर तीन बहुमंजिला इमारतें, एक फार्महाउस और तीन महंगे भूखंड का पता चला। इसके अलावा उनके पास 460 ग्राम सोना और 80 लाख रुपए से अधिक की बैंक जमा राशि मिली।

उन्होंने बताया कि अवैध रूप से हिरण के सींग रखने को लेकर भी कार्यकारी अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जा रही है।

बीसीसीआई यूएई में एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार

नई दिल्ली/ढाका/भाषा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता सितंबर में संक्षिप्त रूप से फिर से शुरू होगी क्योंकि बीसीसीआई के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आगामी एशिया कप टी 20 टूर्नामेंट की मेजबानी करने का रास्ता साफ हो गया है।

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एसीसी की बैठक के बाद यह फैसला हुआ जिसमें सभी 25 सदस्य देशों ने आयोजन स्थल पर चर्चा के लिए हिस्सा लिया। बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व इसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वर्चुअली किया। एसीसी के सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, ''बीसीसीआई यूएई में एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत के अपने सभी मैच दुबई में खेलने की संभावना है। कार्यक्रम पर अब भी विचार-विमर्श चल रहा है।'' यह टूर्नामेंट यूएई में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने 2027 तक सभी बहु राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपने सभी मैच तटस्थ स्थानों पर खेलने के लिए

पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। एशिया कप का यह चरण टी20 प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि खेल के सबसे छोटे प्रारूप का अगला आईसीसी विश्व कप फरवरी 2026 में भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट सितंबर में दो सप्ताह से थोड़ा अधिक समय तक चलेगा। इसे महीने के अंतिम सप्ताह से पहले समाप्त करना होगा क्योंकि इसी समय भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट शृंखला खेलनी है। तीन अंतरराष्ट्रीय मैदानों में से टूर्नामेंट के लिए दुबई और अबुधाबी के इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। प्रसारकों और प्रायोजकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा क्योंकि दोनों टीमों के बीच अगर फाइनल नहीं होता है तो कम से कम दो मैच होंगे (ग्रुप लीग और सुपर सिक्स)। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 'पीटीआई' को बताया, ''हमारे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एसीसी बैठक में शामिल हुए। वह सदस्यों को जानकारी देंगे। में अटकलों पर विश्वास नहीं करता इसलिए आपको कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर पता चल जाएगा।''

इंग्लैंड में जीत से महिला विश्व कप से पहले भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा : तेंदुलकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत की दो शृंखलाओं में जीत से इस साल होने वाले वनडे विश्व कप और अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप से पहले महिला टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने टी20 शृंखला 3-2 से जीत कर नया इतिहास रचा। यह पहला अवसर था जबकि भारतीय महिला टीम ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में इंग्लैंड से शृंखला जीती। भारत ने इसके बाद वनडे शृंखला 2-1 से अपने नाम की। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 30 सितंबर से श्रीलंका के साथ एकदिवसीय विश्व कप की सह-मेजबानी करेगा। इसके बाद इंग्लैंड में 2026 में टी-20 विश्व कप का आयोजन होगा।

तेंदुलकर ने रेडिट पर कहा, ''इंग्लैंड में जीतना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और टी-20 तथा वनडे दोनों में ऐसा करना टीम की तैयारी और मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बयां करता है।'' उन्होंने कहा, ''इस शानदार प्रदर्शन से टीम का आगे होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। दो विश्व कप सामने होने के कारण यह टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी था। शाबाश टीम इंडिया।'' भारत अब 14 सितंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे शृंखला में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा और इसके बाद अपनी धरती पर होने वाले विश्व कप में भाग लेगा।

तेंदुलकर ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सभी खिलाड़ियों ने धैर्य से कम लिया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया।

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने पहले मैच में अपना पहला टी-20 शतक बनाया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत ने तीसरे वनडे में शतक लगाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इसके अलावा 21 वर्षीय क्रांति गौड़ ने तीसरे वनडे में छह विकेट लिए। यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय तेज गेंदबाज और कुल मिलाकर पांचवीं गेंदबाज बन गई।

सुविचार

सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

डिजिटल डकैती: कब लगेगी लगाम?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में साइबर अपराध के कारण देशवासियों को हुए वित्तीय नुकसान का जो आंकड़ा जारी किया, उससे पता चलता है कि डिजिटल ठग बेलगाम होते जा रहे हैं। उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। वे लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। उनका दुस्साहस कितना बढ़ गया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों को 22,845.73 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है! यह आंकड़ा इससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 206 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस राशि से विकास संबंधी कितने ही प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते थे, लेकिन साइबर ठग इसे डकार गए। ठगों द्वारा लूटी गई राशि का 7,465.18 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर 22,845.73 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच जाना अत्यंत चिंता का विषय है। हमारे देश में उच्च स्तर की जांच एजेंसियां हैं। सरकार के पास कुशल तकनीकी विशेषज्ञ हैं। इसके बावजूद साइबर अपराधियों की पौ-बारह हो रही है! आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 में साइबर अपराधियों द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी की 36,37,288 घटनाएं एनसीआरपी और सीएफसीएफआरएमएस पर दर्ज की गई थीं। इससे पिछले वर्ष ऐसी 24,42,978 घटनाएं हुई थीं। ये वो आंकड़े हैं, जो दर्ज हुए हैं। कई लोगों को शिकायत दर्ज कराने के बारे में जानकारी नहीं होती या ठगी की राशि छोटी होती है तो वे शिकायत दर्ज नहीं कराते। ऐसे में असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। हाल में दूरसंचार सेवाएं देने वाली कुछ कंपनियों ने ठगी संबंधी कॉल्स को प्रतिबंधित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अगर इस तकनीक पर पहले काम किया गया होता तो लोगों की कमाई ज्यादा सुरक्षित होती।

सवाल है- साइबर ठगी की घटनाओं पर लगाम कैसे लगाई जाए? इसके लिए कई स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। साइबर ठगी संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्प लाइन अच्छा काम कर रही है। इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों को शिकायत दर्ज कराने में ज्यादा समय न लगे। वहीं, दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियों को उन कॉल और सिम कार्ड को प्रतिबंधित करने में तेजी लानी चाहिए, जिनका संबंध साइबर ठगी से हो। पुलिस और जांच एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। उनका पर्दाफाश करना चाहिए। साथ ही, उन्हें निश्चित अवधि में कठोर दंड मिलना चाहिए। हाल में उत्तर प्रदेश में एक साइबर ठग को 14 महीने के अंदर सजा मिलने का मामला चर्चा में रहा था। वह लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनके बैंक खाते खाली कर देता था। उसने एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 85 लाख रुपए हड़पे थे। उस ठग को सात वर्ष की सजा हुई है। अगर साइबर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें इस तरह सजा मिलने लगे तो वे जरूर हतोत्साहित होंगे। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। पिछले डेढ़ दशक में साइबर अपराधियों ने नए-नए तरीके ढूंढकर लोगों को ठगा था। कभी लॉटरी लगने, केबीसी में इनाम जीतने, लकी नंबर खुलने का झांसा देकर खूब लूटा गया था। उसके बाद मोबाइल टावर, किसी खास योजना का लाभ, सस्ता लोन, डिजिटल दोस्ती, सोने के बिस्किट के नाम पर चूना लगाया गया। आश्चर्य की बात है कि सरकार द्वारा सावधान किए जाने के बावजूद रोजाना ही कई लोग साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं। भविष्य में ठग कोई और तरीका ढूंढ़ेंगे। इससे बचने के लिए जनता को खबरें पढ़ने की आदत डालनी होगी। जो लोग समसामयिक घटनाओं से अवगत होंगे, वे साइबर ठगी की घटनाओं से ज्यादा सुरक्षित होंगे।

ट्वीटर टॉक

संसदीय कार्यवाही को बाधित करना हमारी मंशा नहीं होनी चाहिए। सदन में बैठकर हम अपने लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे व्यवहार, आचरण को करोड़ों देशवासी देखते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है, दुनिया के देश हमारा अनुसरण करते हैं।

-ओम बिरला

सभी प्रदेशवासियों को श्रावणी हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस सुअवसर पर वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सदैव खुशियों से हरा-भरा रहे।

-दीया कुमारी

धन्ना तलाई क्षेत्र मे ड्रेनेज सिस्टम एवं सौंदर्यीकरण कार्यो का शिलान्यास किया। करीब 2 करोड़ की लागत से शुरू किए जा रहे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा और उसे सुदृढ़ बनाया जाएगा, जिससे पानी का ठहराव नहीं होगा।

-सचिन पायलट

प्रेरक प्रसंग

ब्रह्मांड का दर्शन

चरक विषय की कक्षा चल रही थी। एक छात्र ने जिज्ञासा से पूछा, 'आत्रेय ऋषि ने अग्निवेश को कहा था कि मनुष्य लोक का प्रतिबिंब है। इसका क्या अर्थ है?' शिक्षक ने पुनर्वसु आत्रेय के उपदेशों का आधार लेते हुए कहा, 'वत्स! यह मनुष्य केवल एक देह नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्पण है। जैसे बाहर का जगत है, वैसा ही एक विराट संसार उसके भीतर भी विद्यमान है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में वायु उत्साह का स्रोत है, उसी प्रकार शरीर में प्राणवायु जीवन को गति देती है। विश्वदेव जैसे समस्त देवगण ब्रह्मांड में विविध कार्यों के संचालक हैं, वैसे ही हमारे शरीर में सभी इन्द्रियां और उनके विषय (स्वर, स्पर्श, रूप, रस, गंध) मिलकर जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे ब्रह्मांड में कहीं अंधकार है, वैसे मनुष्य में भी मोह का अंधकार होता है।' शिष्य ने पूछा 'क्या मेरे भीतर देवता भी हैं?' शिक्षक ने कहा 'तेरे भीतर इन्द्र का आत्मविश्वास है, रुद्र का रोष है, सोम की शीतलता है। तेरे हंसने पर अष्टवसुओं का सुख झलकता है। तेरा प्रेम अश्विनियों की शोभा से दमकता है। मनुष्य की बाल्यावस्था कृतयुग, यौवन त्रेता, वृद्धावस्था द्वापर और रोगों से घिरा काल कलियुग है और मृत्यु युगांत है।'

सामयिक

कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?

अशोक भाटिया

मोबाइल : 9221232130

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ गई है। संविधान में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाहक का प्रावधान नहीं है इसलिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सोमवार रात दिए गए इस्तीफे से देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद खाली हो गया है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई है। वे भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले केवल तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वीवी गिरि और आर वेंकटरमन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद क्रमश: गोपाल स्वरूप पाठक और शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने थे। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रविधान नहीं है। हालांकि, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए, संविधान के अनुसार रिक्त पद को छह महीने के भीतर भरना आवश्यक है लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि पद रिक्त होने के बाद यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करेगा। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत होता है। परंपरा के अनुसार, संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा न कि केवल धनखड़ का शेष कार्यकाल।

जगदीप धनखड़ का अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज होने के बाद अब इस अहम पद के लिए नए नामों की चर्चा शुरू हो गई है और कई बड़े लोगों के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। अब इसमें एक और चौंकाने वाला नाम जुड़ गया है - केंद्रीय राज्य मंत्री और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर। बुधवार शाम को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें और तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि एनडीए रामनाथ ठाकुर को इस पद पर बैठाकर कई सियासी संदेश देना चाहती है, खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। ज्ञात हो कि रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वह राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, और कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वे लालू यादव की पहली कैबिनेट में गन्ना मंत्री रह चुके हैं और बाद में 2005 से 2010 तक नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। इस समय वे मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। उनके पिता को हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया है, जिससे उनके परिवार का राजनीतिक कद और बढ़ गया है। उपराष्ट्रपति पद की रेस में उनका नाम आना बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है।

रामनाथ ठाकुर के अलावा भी कई और नाम संभावित उपराष्ट्रपति की रेस में हैं। इनमें हरिवंश नारायण सिंह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसे नाम सामने आए हैं। हालांकि, बीजेपी की रणनीति को देखते हुए किसी चौंकाने वाले नाम की घोषणा भी मुमकिन है। मोदी सरकार अक्सर आखिरी वक्त में ऐसा नाम सामने लाती है जिसकी उम्मीद कम ही होती है। अब सबकी निगाहें बीजेपी की ओर हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा - क्या रामनाथ ठाकुर पर दांव चलेगी बीजेपी? गौरतलब है कि हैरान बीजेपी के अंदर भी कुछ अलग चर्चाओं का दौर जारी है। अलग-अलग खेमे में अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। मसलन, जब एनबीटी ऑनलाइन ने दिल्ली में बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने नाम की गोपनीयता की शर्त पर कहा कि 'हो सकता है कि यह चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव तक टल जाए। क्योंकि, इसे करवाने की इतनी जल्दी नहीं लग रही।' उन्होंने संभावना जताई कि 'अगर बिहार चुनाव तक यह टल जाता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं।' लेकिन, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर राज्यसभा के उपसभापति हरवंश के नाम पर दिया। उनका कहना है कि 'नीतीश की जेडीयू अबकी बार जो एनडीए में आई है तो उसमें हरिवंश ही बड़े किरदार रहे हैं।' इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से दावा किया कि जो भी होगा, वह 'बिहार का हो सकता है।'

इधर कांग्रेस के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने के संकेत दे रहे हैं। इसे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के नए दौर का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया से कहा कि यह एक चुनाव की प्रक्रिया नहीं, वैचारिक लड़ाई है। हम सरकार के कदम का इंतजार कर रहे हैं और इंडिया ब्लॉक ही नहीं, इससे बाहर के विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का यह भी दावा है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामान्य नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि न फेयरवेल हुआ, ना ही फेयरवेल स्पीच। बस अचानक एग्जिट हो गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार वार्ता की। कांग्रेस का मानना है कि राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति से जो राजनीतिक तूफान आया, उसमें फंसकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। विपक्ष के सूत्रों की मानें तो राज्यसभा में दो जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए थे। एक जस्टिस यशवंत वर्मा और दूसरा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। जगदीप धनखड़ ने इन्हें स्वीकार करने से बचने के लिए इस्तीफा दिया होगा।

मंथन

हंगामा करने वालों को हंगामे का बहाना चाहिए

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे का शिकार हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। सोमवार और मंगलवार को दो दिन की कार्यवाही पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की भेंट चढ़ गया। बाद में बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की बैठक में 32 घंटे की चर्चा का फैसला हुआ। लगा कि अब दोनों सदन सुचारु रूप से चलेंगे। मगर तीसरे और चौथे दिन भी दोनों सदन सुचारु नहीं हुए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में जमकर हंगामा किया। एनडीए के सांसदों की तरफ से कार्यवाही को शांत करने की अपील की गई, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चारों दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार-बार बाधित हुई ।

ऐसा लगता है विपक्ष का एकमात्र काम हंगामा ही रह गया है। किसी न किसी बहाने संसद में हंगामा करना स्वस्थ बहस से ज्यादा जरुरी हो गया है। विरोध का भी एक तरीका होता है। कहावत है पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए और हंगामा करने वाले को हंगामे का बहाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का मामला पटरी पर आया तो ज्वलंत प्रकरण हंगामा शुरू कर दिया । साफ है कि विपक्ष को संसद ठप करने का बहाना चाहिए। सच तो यह है कांग्रेस उन मसलों की खोज करती दिख रही है जिनके जरिये हंगामा किया जा सके और अब हंगामे का मतलब किसी मसले पर सरकार से जवाब मांगना या किसी मसले पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संसद में ऐसे हालात पैदा करना होता है जिससे वहां कोई काम ही न हो सके। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि देश संसद चलने की बाट जोहे और कुछ राजनीतिक दल अपना सारा जोर संसद को न चलने देने में लगाएं। यह सही है कि संसद सत्र पहले भी बर्बाद हुए हैं। मगर अब हर छोटी मोटी बात पर संसद में हंगामा मामूली बात रह गया है।

पिछले कई सालों की संसद की कार्यवाही पर नज़र डालें तो देखेंगे हर सत्र शुरू होते ही विपक्ष अपने कुछ मुद्दों पर कार्यवाही रोककर सबसे पहले चर्चा करने पर अड़ जाता है और अध्यक्ष या सभापति संसद को नियमानुसार चलाने पर जोर देते है। यहीं से पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते है और संसद ठप्प हो जाती है। स्पीकर कहते है सदन आपका है, सबका है और देश भी चाहता है कि संसद चले। स्पीकर विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते हुए कहते है कि हर विषय, हर मुद्दे पर नियम-प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा मगर स्पीकर की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं होता और संसद बिना कोई विधि सम्मत कार्यवाही के हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शायद ही संसद का कोई सत्र ऐसा रहा हो, जिसका आधे से ज्यादा समय हंगामे में ज़ाया न हुआ हो। संसद में बार-बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि सदन के अहम सत्र हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं। भारतीय राजनीति में विपक्ष का अर्थ, जो सत्ता में नहीं है,से है। विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वस्थ विपक्ष का कार्य सरकार की सकारात्मक तरीके से आलोचना करना होना चाहिए। स्वस्थ विपक्ष के रूप में विपक्ष को जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना व बहस करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पक्ष और विपक्ष में जो कटुता देखने को मिली वह लोकतंत्र के हित में नहीं कही जा सकती। इससे हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली का ह्रास हुआ है। आज सत्ता और विपक्ष के आपसी सम्बन्ध इतने खराब हो गए है की आपसी बात तो दूर एक दूसरे को फूटी आँख भी नहीं सुहाते। दुआ सलाम और अभिवादन भी नहीं करते। लोकतंत्र की सफलता पक्ष और विपक्ष की मजबूती में है। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब राष्ट्रीय हितों के मामलों में दोनों की एक राय हो। देश सबसे बड़ा है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है जो दुखद है। अब समय का तकाजा है सभी राजनीतिक पार्टियों में जो कुछ गंभीर और समझदार नेता बचे हैं वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभ्यता और मर्यादा बनाए रखने के लिए कोशिशें शुरू करें।

नजरिया

एकता व समता के संवर्धक आचार्य आनंदऋषि

डॉ. दिलीप धींग

मोबाइल : 9952048107

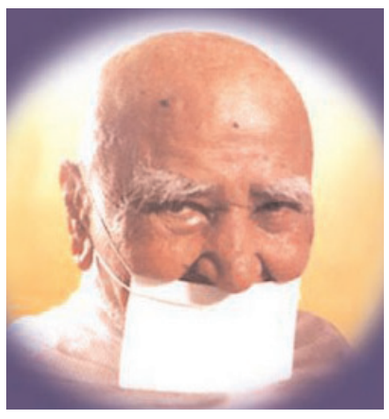

भारतीय ऋषि परम्परा के देदीप्यमान नक्षत्र आचार्य आनन्दऋषिजी महाराज का जन्म श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, वि.सं. 1957, शुक्रवार 27 जुलाई 1900 को चिचोंडी (महाराष्ट्र) में हुआ। उनके बचपन का नाम नेमीचन्द था। बचपन में ही उन्हें पिता सुश्रावक देवीचन्दजी गुगलिया का चिर-वियोग झेलना पड़ा। सुश्राविका माता हुलासबाई के त्याग-तप से अनुप्राणित जीवन का नेमीचन्द के बालमन पर गहरा असर हुआ। एक बार श्री रत्नऋषिजी महाराज का चिचोंडी में पदार्पण हुआ। माँ ने अपने छोटे बेटे नेमीचंद को सामायिक, प्रतिक्रमण आदि सीखने के लिए रत्नऋषिजी के पास भेजा। धर्मप्राण माँ के द्वारा ज्ञान-ध्यान सीखने की मंगल प्रेरणा का बीज सुयोग्य गुरु और विनयवान शिष्य का सुयोग पाकर खूब पल्लवित-पुष्पित हुआ। प्रतिभाशाली मुमुक्षु नेमीचन्द ने वि.सं. 1970 की मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी (7 दिसम्बर 1913) रविवार को मिरीगाँव (महाराष्ट्र) में श्री रत्नऋषिजी से जैन आर्हती दीक्षा अंगीकार कर ली और 'आनन्दऋषि' बन गये। जिस उद्देश्य से उन्होंने श्रमण-जीवन अंगीकार किया, उस उद्देश्य की आराधना में वे अप्रमा भाव से जुट गये। गुरु की आज्ञा और निश्रा में उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, आगम, न्याय, व्याकरण आदि तथा स्वसमय और परसमय का दाचिा होकर अध्ययन किया। अध्यापन में पं. राजधाँरी त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा। निर्मल प्रज्ञा के धनी मुनि श्री आनन्दऋषि ने अल्प समय में ही प्रचुर ज्ञानार्जन कर लिया।

वि. सं. 1988 (सन 1931) में मनमाड़ में उनका जैन दिवाकर मुनि चौथमलजी से मिलन हुआ। तब दिवाकरजी ने आनन्दऋषिजी में भावी आचार्य की योग्यता और संभावना देखीं। उस समय दिवाकरजी ने उपाध्याय प्यारचन्दजी महाराज से कहा कि जब भी स्थानकवासी सम्प्रदायों का एकीकरण हो और आचार्य बनाने की बात आए, तो आनन्दऋषिजी को आचार्य बनाना। युवावस्था में ही आनन्दऋषिजी का ज्ञान-ध्यान और व्यवहार इतना प्रभावशाली बन गया था कि जैन दिवाकरजी ने उनको अपने दूरदर्शितापूर्ण समन्वयकारी विचार के साथ संयोजित कर लिया। वि.सं. 1993 में भुसावल (महाराष्ट्र) में आनन्दऋषिजी, ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य बने। वि. सं. 1999, माघ कृष्ण 6, बुधवार को उन्हें पाथर्डी (महाराष्ट्र) में ऋषि संप्रदाय के आचार्य पद पर अभिषिक्त किया गया। दिवाकरजी के कथनानुसार वि. सं. 2006, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को राजस्थान के ब्यावर में आनन्दऋषिजी को पाँच सम्प्रदायों के एकीकरण के फलस्वरूप बने 'वीर वर्द्धमान श्रमण संघ' का आचार्य बनाया गया। बाद में वे वि. सं. 2021, फाल्गुन शुक्ल 11 को अजमेर (राजस्थान) में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के आचार्य बने। इस प्रकार जैन दिवाकरजी की भावना पूर्ण रूप से साकार हुई।

इससे पूर्व सादड़ी (राजस्थान) में वि. सं. 2009, वैशाख शुक्ल तृतीय (आखा तीज) को श्रमण संघ के निर्माण के समय उन्हें संघ का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था। विशाल एकता के उस प्रसंग पर उन्होंने अपने पूर्व पदों का सहज सहर्ष विसर्जन कर दिया था। उनके अनुार ज्ञान-ध्यान का मूल्यांकन करते हुए वि. सं. 2013 में, 1 अप्रेल 1956 को उन्हें भीनासर (बीकानेर, राजस्थान) में श्रमण संघ के उपाध्याय पद पर आरूढ़ किया गया। उन्होंने अपने पूर्व पट्टधर आचार्य आत्मारामजी की तरह एवं समकालीन आचार्य हस्तीमलजी की तरह मुनि, उपाध्याय और आचार्य, तीनों पदों का गौरव बढ़ाया। धार्मिक इतिहास में प्राय: यह देखा गया है कि कोई भी धर्मसंघ किसी सम्प्रदाय से टूटकर या अलग होकर बना है। लेकिन श्रमण संघ एक ऐसा विलक्षण धर्मसंघ है, जिसका निर्माण अनेक सम्प्रदायों के जुड़ने से हुआ है। इस संघ के बुनियाद में ही एकता और मैत्री है। श्रमण संघ के द्वितीय आचार्य आनन्दऋषिजी ने इस बुनियाद को दृढ़तर बनाने में अद्वितीय योगदान किया। श्रमण संघ के आचार्य पद पर आसीन होने के बाद तीन दशक तक उन्होंने संघ का अविस्मरणीय कुशल नेतृत्व किया। उनके आचार्यकाल में श्रमणसंघ ने चहुँमुखी विकास के नये प्रतिमान स्थापित किये। उनकी नेतृत्व कुशलता, अनुशासनप्रियता, ऋजुता और मृदुता अद्भुत थी। संघ एकता के साथ ही वे जैन एकता और मानव एकता के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे।

उनका सम्पूर्ण जीवन मैत्री, सद्भाव और समन्वय के अभिवर्द्धन को समर्पित रहा। उन्होंने अपने गहरे सद्भाव और निर्मल साधना से जीवन और समाज के अनेक अप्रिय प्रसंगों को भी प्रिय और प्रेरक बना दिया। उनकी ऊँचे दर्जे की सरलता और साधना की तेजस्विता के समक्ष वक्त और व्यक्ति, दोनों अनुकूल हो जाते थे। एकता, समता, संगठन और अनुशासन के प्रेरक प्रतिमान आचार्यश्री ने हमेशा रचनात्मकता पर ध्यान दिया और सकारात्मक बने रहे। उनकी रचनात्मकता अनेक आयामों में अभिव्यक्त हुई। बहुश्रुत आचार्य श्री आनन्दऋषिजी को बचपन में भजन-कीर्तन में बहुत रुचि थी। जिस प्रकार उन्हें संस्कृत और प्राकृत की अनगिनत गाथाएँ कण्ठस्थ थीं, उसी प्रकार तुकाराम और एकनाथ जैसे अनेक सन्त-कवियों के काव्य भी कण्ठस्थ थे। उनके प्रवचनों में ज्ञान, भाषा और संस्कृति की इन्द्रधनुषी छटाएँ विद्यमान रहती थीं। आचार्य देवेन्द्रमुनिजी ने आचार्य आनन्दऋषिजी के प्रभावशाली प्रवचनों की तुलना महात्मा गांधी के प्रवचनों से की। उनके प्रवचन 'आनन्द प्रवचन' नामक पुस्तक श्रृंखला में बारह भागों में प्रकाशित और लोकप्रिय हुए।

बहुभाषाविद आचार्यश्री को ज्ञान से बहुत प्रेम था। समाज में बुनियादी परिवर्तन के लिए वे विद्या और विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उनकी पुनीत प्रेरणा से श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड सहित दर्जनों संस्थाएँ जैनविद्या और प्राच्यविद्या के शिक्षण, शोध, लेखन और प्रचार के लिए स्थापित हुईं। फरवरी-1975 में जब आचार्यश्री का राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव मनाया गया तो उन्हें जो अभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया गया तो उसका नाम 'जैनविद्या एवं प्राकृत भाषा ज्ञान कोष' रखा गया। मई-1987 में उनकी पुनीत सन्निधि में पूना (महाराष्ट्र) में विशाल ऐतिहासिक संत सम्मेलन हुआ। उनकी 79वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिसम्बर 1991 को हैदराबाद में आचार्य आनंदऋषि साहित्य निधि की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा व साहित्य की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष 'आचार्य आनंदऋषि साहित्य पुरस्कार' प्रदान किया जाता है। 28 मार्च 1992 (चैत्र कृष्ण 10, वि.सं. 2048) शनिवार को अहमदनगर (महाराष्ट्र) में आचार्यश्री अपनी नश्वर देह छोड़ देवलोकगमन कर गये। 9 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में चार रुपये मूल्य-वर्ग का बहुरंगी डाक-टिकट जारी किया। डाक-टिकट में अहिंसा धर्मचक्र के साथ उन्हें चित्रित किया गया। उनकी पुनीत स्मृतियों में देशभर में शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, साधना, मानवसेवा, जीवदया, लोक कल्याण को समर्पित अनेक संस्थाएँ और योजनाएँ गतिमान हैं।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

सेल्फी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गुरुवार को डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ।

अफगानिस्तान में उच्च शिक्षा के लिए तरसतीं लड़कियां, छठी कक्षा से आगे पढ़ाई करने पर है पाबंदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

काबुल। नाहिदे स्कूल से आने के बाद हर दिन छह घंटे एक कब्रिस्तान में काम करती है, पास की एक दरगाह से पानी इकट्ठा करती है और कब्रों पर शोक मनाने आने वालों को पानी बेचती है।

नाहिदे का सपना है कि वह डॉक्टर बने लेकिन उसे यह मालूम है कि यह ख्वाब फिलहाल पूरा नहीं होने वाला क्योंकि जब स्कूल का अगला सत्र शुरू होगा तो कुरान और इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए एक मदरसे में उसका दाखिला करा दिया जाएगा। नाहिदे ने कहा, ''मुझे स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मैं नहीं जा पाउंगी, इसलिए मैं मदरसे जाऊंगी।''

नाहिदे ने कहा, ''अगर मैं स्कूल जाती तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाती। लेकिन मैं नहीं बन सकती।''

नाहिदे की गहरी भूरी आंखों में सपना पूरा नहीं हो पाने की मायूसी साफ झलक रही थी।

तेरह साल की नाहिदे प्राथमिक विद्यालय की आखिरी कक्षा में है। अफगानिस्तान में छठी कक्षा के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा उनके पहनावे और कहीं आने-जाने को लेकर भी पाबंदियां हैं।

उच्च शिक्षा हासिल करने का कोई विकल्प नहीं होने के कारण, कई लड़कियां मदरसों का रुख कर रही हैं। काबुल में स्थित 'तरनीम नसरत इस्लामिक साइंसेज एजुकेशनल सेंटर' के निदेशक जाहिद-उर-रहमान साहिबी ने कहा, ''चूंकि स्कूल लड़कियों के लिए बंद हैं, इसलिए वे इसे एक अवसर के रूप में देखती हैं।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए, वे यहां धर्मशास्त्र की शिक्षा हासिल करने और अध्ययन करने के लिए आती हैं।''

इस केंद्र में लगभग 400 छात्राएं हैं, जिनकी आयु लगभग तीन से 60 वर्ष के बीच है। वे कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र, पैगंबर मोहम्मद के कथनों और अरबी का अध्ययन करती हैं।

अफगानिस्तान में महिलाओं के माध्यमिक और उच्च शिक्षा हासिल करने पर प्रतिबंध विवादास्पद रहा है, यहां तक कि इसको लेकर तालिबान के अंदर से भी असहमति के स्वर उठे। उपविदेश मंत्री शेर अब्बास स्तानिकजई ने जनवरी में एक सार्वजनिक संबोधन में कहा था कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है।

हालांकि तालिबान नेतृत्व को कथित रूप से उनका यह बयान पसंद नहीं आया और अब वह आधिकारिक रूप से छुट्टी पर हैं। माना जाता है कि उन्होंने देश छोड़ दिया है।

इंदौर में जन्मी दो सिर वाली बच्ची, जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे चिकित्सक

इंदौर (मध्यप्रदेश)/भाषा। इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में 22 वर्षीय महिला ने एक ही धड़ से जुड़े दो सिरों वाली बच्ची को जन्म दिया। जन्मजात विकृति के कारण जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही बच्ची की जान बचाने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ कड़ी जद्दोजहद में जुटे हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पड़ोस के देवास जिले की इस महिला ने इंदौर के शासकीय महाराजा तुकोजीराव चिकित्सालय (एमटीएच) में मंगलवार को सिजेरियन ऑपरेशन के जरिये ऐसी बच्ची को जन्म दिया जिसके एक ही धड़ से जुड़े दो सिर हैं। उन्होंने बताया कि 2.80 किलोग्राम किलोग्राम वजनी बच्ची को नवजात शिशुओं की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया है।

बांग्लादेश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश को राजद्रोह व जालसाजी के मामलों में हिरासत में लिया गया

ढाका/भाषा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एबीएम खैर-उल-हक को राजद्रोह के आरोप सहित तीन आपराधिक मामलों में बृहस्पतिवार को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हक 2010 से 2011 तक देश के 19वें प्रधान न्यायाधीश रहे थे। उन्हें ऐतिहासिक फैसले सुनाने के लिए जाना जाता है। उनकी अगुवाई वाली पीठ ने 2011 में व्यवस्था देते हुए बांग्लादेश की गैर-दलीय कार्यवाहक सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस के उपायुक्त तालिब-उर-रहमान ने संवाददाताओं को बताया कि जासूसी शाखा के अधिकारियों ने 81 वर्षीय पूर्व न्यायाधीश को राजधानी के धनमंडी इलाके में उनके आवास से हिरासत में लिया।

रहमान ने कहा, हक तीन मामलों में आरोपी हैं। कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश को अदालत में पेश करने से पहले कम से कम एक मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

उनके खिलाफ मामले अगस्त 2024 में विभिन्न वकीलों द्वारा दायर किए गए थे। ये पांच अगस्त को स्टूडेंटस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) के नेतृत्व में हिंसक आंदोलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के फौरन बाद दायर किए गए थे।

उस समय हक विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। हालांकि उन्होंने 13 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया था।

ढाका में दायर पहले मामले में उन पर कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था से संबंधित 13वें संवैधानिक संशोधन को रद्द करने वाले फैसले को कथित रूप से बदलने में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

एक सप्ताह बाद, इसी मुद्दे पर राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित नारायणगंज में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा ढाका में एक अन्य वकील द्वारा उनके कथित भ्रष्ट आचरण, अवैध और धोखाधड़ी वाले निर्णयों के संबंध में एक और मामला दर्ज कराया।

थाईलैंड, वियतनाम में आयोजित की गई बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने पिछले दो वर्षों में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की दो प्रमुख प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली प्रदर्शनी 22 फरवरी से 19 मार्च, 2024 तक थाईलैंड में आयोजित की गई, जिसमें भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेषों को चार स्थानों पर प्रदर्शित किया गया। लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। दूसरी प्रदर्शनी 2 मई से 2 जून, 2025 तक वियतनाम में आयोजित की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा से लाए गए पवित्र अवशेष वेसाक उत्सव के दौरान नौ स्थलों पर प्रदर्शित किए गए।

गुरुवार को सूरत के कंथेरिया हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने एक लाख पच्चीस हज़ार रुद्रकों से शिवलिंग बनाया।

पवन कल्याण की फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' रिलीज हुई

अमरावती/भाषा

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' बृहस्पतिवार को देशभर में रिलीज हुई। फिल्म के रिलीज के दौरान विजयवाड़ा, कोनासीमा और कडप्पा समेत आंध्र प्रदेश के कई सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में प्रशंसक जमा हुए। प्रशंसकों ने केक काटे, पटाखे फोड़े और बैनर लगाकर फिल्म की रिलीज का जश्न मनाया। यह पवन कल्याण के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली फिल्म है।

ए.एम. ज्योति कृष्ण और कृष जगर्लामुडी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में निधि अग्रवाल और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं। संगीत एमएम कीरवनी का है और फिल्म का निर्माण मेगा सूर्या प्रोडक्शन ने किया है। राज्य सरकार ने फिल्म की टिकट दरों में बढ़ोतरी की अनुमति दी है। टिकट का मूल्य सिंगल स्क्रीन में 100 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 300 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक हफ्ते तक सभी स्क्रीन पर दिन में पांच शो दिखाने की अनुमति दी गई है। फिल्म के रिलीज से पहले विशाखापट्टनम में 23 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रशंसक, सिनेमा तथा राजनीति से जुड़ी हस्तियां शामिल हुईं। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशंसकों से संवाद किया और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रभावशाली लोगों के साथ अपनी बातें साझा कीं। कल्याण ने कहा कि 'हरि हर वीरा मल्लू' की रिलीज कई बार टली, जिसका कारण कोविड-19 महामारी और उनकी राजनीतिक व्यस्तताएं रहीं।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने भारतीय प्रदर्शन कलाओं की दृष्टि से रामायण पर बनी डॉक्यूमेंट्री जारी किया

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 'रामायण' की परंपराओं और कथाओं से जुड़ी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'कण-कण में राम' जारी किया। यह फिल्म भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास (इंटैक) के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई। 'कण-कण में राम' शीर्षक वाली इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के विभिन्न हिस्सों में रामायण के प्रस्तुतीकरण को दर्शाया गया है जिसमें अनुष्ठानात्मक प्रदर्शन, नृत्य-नाट्य और कठपुतली कला जैसी विविध विधाएं शामिल हैं। शेखावत ने कहा कि यह फिल्म लोगों से आग्रह करती है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से न देखें। 'कण-कण में राम' का अर्थ है कि उनके चरित्र से स्थापित जीवन के सिद्धांत हमारे सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से रचे-बसे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''इस डॉक्यूमेंट्री में आपको भारतीय संस्कृति के उन पहलुओं का भी परिचय मिलेगा जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती या जिनके बारे में जानकारी कम है। यह डॉक्यूमेंट्री ज्ञान और कला के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कृति है। आप भी इसे देखें और दूसरों को भी इसके विषय में अवगत कराएं। इंटैक को इस अद्भुत रचनात्मकता के लिए बहुत-बहुत बधाई!''

संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री में रामायण की परंपराओं और कथाओं से जुड़ी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया है। फिल्म में जिन प्रमुख परंपराओं को दिखाया गया है, उनमें कर्नाटक की यक्षगान और उप्पिनीकुद्रु कठपुतली परंपरा, ओडिशा की लंका पोड़ी यात्रा और रावण छाया, असम की सत्रिया परंपरा, राजस्थान की मेवाती भपंग प्रस्तुति और छत्तीसगढ़ का रामनामी समाज शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, यह फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में भगवान राम की सर्वव्याप्त सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपस्थिति को उजागर करती है और यह दिखाती है कि उनकी कहानियां और शिक्षाएं धार्मिक दृष्टिकोण से परे जाकर मानवता को जोड़ती हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय प्रदर्शन कलाओं की दृष्टि से रामायण की विरासत और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाने का अवसर था।

एआर रहमान के साथ नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे सुभाष घई, बोले- 'मुझे जादू पर भरोसा'

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई जल्द ही एआर रहमान के साथ कुछ नया म्यूजिकल प्रोजेक्ट लेकर आने को तैयार हैं। घई ने सोशल मीडिया पर म्यूजिक कंपोजर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को जानकारी दी। सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर एआर रहमान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, संगीत का जादू तभी होता है जब रचनात्मकता, प्यार और पैशन की तलाश एक साथ मिलती है। मैं रहमान से सहमत हूं, जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। जब हम मिलते हैं तो हमारी आत्माएं संगीतमय हो जाती हैं। देखते हैं, अब हम क्या लेकर आ रहे हैं? मुझे बस जादू पर भरोसा है।

घई ने अपने पोस्ट में रहमान के साथ नए प्रोजेक्ट का संकेत दिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच उत्साह देखने को मिला। एक यूजर ने लिखा, उत्साहित हैं, हमें इंतजार है।

दूसरे यूजर ने लिखा, ताल मिट्स राग। सुभाष घई और एआर रहमान पहले भी कई फिल्मों के लिए साथ में काम कर चुके हैं, जिनमें 'ताल', 'किसना' और 'युवराज' शामिल हैं। इनमें से 'ताल' का संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। साल 2024 में फिल्म 'ताल' की 25वीं सालगिरह पर मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सुभाष घई ने बताया कि रहमान ने 'ताल' के लिए बहुत कम फीस ली थी। इस पर रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा था, इस बारे में बात नहीं करनी है। वहीं, सुभाष घई ने हाल ही में अपनी अगली फिल्म की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रितेश देशमुख की एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि वह उनकी फिल्म की 'नायिका' हैं।

उन्होंने रितेश को क्लासिक सुंदरता भी बताया। साथ ही 'खूबसूरत लड़की' का नाम गेस करने को कहा। शेयर की गई तस्वीर साल 2006 की कॉमेडी फिल्म 'अपना सपना मनी मनी' की है, जिसमें रितेश ने एक ठग के किरदार में महिला का वेश धारण किया था।

नई वेब सीरीज के लिए शिवांगी वर्मा उत्साहित, कहा- मेरा किरदार करेगा सरप्राइज

मुंबई/एजेन्सी

'तेरा इश्क मेरा फितूर', 'छोटी सरदारनी' और 'बैडएस रविकुमार' जैसे प्रोजेक्टस में काम कर चुकीं एक्ट्रेस शिवांगी वर्मा जल्द ही नई वेब सीरीज में नजर आएंगी, जिसका हिस्सा बनकर वह बेहद उत्साहित हैं। यह सीरीज 'हंगामा' प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और इसमें एक्शन, ड्रामा, प्यार और कई ट्विस्ट्स हैं। शिवांगी ने कहा, मैं इस नई सीरीज का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। मेरा किरदार बहुत ही मजेदार, मुश्किल भरा और चुनौतीपूर्ण है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, वरना कहानी का राज खुल जाएगा। यह सीरीज एक्शन, ड्रामा, प्यार और सरप्राइज से भरपूर है। आप देखकर हैरान होंगे कि एक लड़की मुश्किल हालात में क्या-क्या कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह किरदार उनके लिए खास है। शिवांगी ने बताया, मैं हमेशा से वेब सीरीज की फैन रही हूं। यह एक्टिंग का ऐसा माध्यम है, जो भावनाओं और किरदार के विकास को गहराई से दिखाने का मौका देता है। जब मुझे इस कहानी के बारे में बताया गया, तो मैं बहुत उत्साहित हो गई। यह किरदार वैसा ही है, जैसा मैं निभाना चाहती थी - मजेदार और सरप्राइज से भरा। शिवांगी ने को-एक्टर्स की तारीफ करते हुए कहा कि शानदार टीम के साथ काम करना इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाता है। उन्होंने बताया, जब आपके साथ टैलेंटेड और अनुभवी कलाकार हों, तो स्क्रीन पर केमिस्ट्री साफ दिखती है। यह पूरी सीरीज को खास बना देता है। उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में बताने से इनकार किया, हालांकि थोड़ा हिंट देते हुए कहा, मेरा लुक ग्लैमरस और आकर्षक है। यह सीरीज एक मसाला जॉनर है, जिसमें हर तरह का मनोरंजन है। शिवांगी ने को-स्टार शरद मल्होत्रा के साथ काम करने के अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने बताया, शरद के साथ काम करना शानदार रहा।

मैं अपने ही घर में उत्पीड़न का शिकार : तनुश्री दत्ता

नई दिल्ली/भाषा

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट कर आरोप लगाया है कि उन्हें सात साल से उनके घर में परेशान किया जा रहा है। अभिनेत्री ने इसी के साथ गुहार लगाई कि 'इससे पहले कि बहुत देर हो' उनकी मदद की जाए। तनुश्री ने ही सबसे पहले अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ शिकायत की थी जिससे सोशल मीडिया पर हैशटैग 'मीटू' आंदोलन की शुरुआत की थी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट में कहा कि उन्हें इतना परेशान किया गया है कि वह बीमार पड़ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उत्पीड़न ''2018 के हैशटैग मीटू' के बाद से चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस को फोन करना पड़ा और पुलिस ने उन्हें 'उचित शिकायत' दर्ज करने के लिए कहा है। अभिनेत्री ने रोते हुये एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया और कैप्शन लिखा, ''कृपया कोई मेरी मदद करें! इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करें।''

परेशान दिख रही अभिनेत्री ने कहा, ''दोस्तों, अपने ही घर में मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मुझे अपने ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को फोन किया और उसने मुझे उचित शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना आने को कहा है... मैं शायद कल या परसों जाऊंगी।''

तनुश्री ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और काम करने में असमर्थ हैं, उनका घर बिखरा हुआ है और घरेलू सहायिका नहीं रख सकतीं। अभिनेत्री ने वीडियो संदेश में किसी का नाम लिए बिना कहा, ''मेरा घरेलू सहायिकाओं के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा है, जो घर में आती हैं वह चोरी करती हैं, तथा अन्य काम करती हैं। लोग मेरे घर का दरवाजा पीटते हैं। मैं परेशान हो रही हूं, कृपया मेरी मदद करें।'' अभिनेत्री ने कहा, ''मैं इमारत के प्रबंधन से शिकायत करते-करते थक गयी और कुछ साल पहले हार मान ली। अब मैं बस इसी के साथ रहती हूं और अपना ध्यान भटकने से रोकने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हेडफोन से हिंदू मंत्रों को सुनती हूं।'' अभिनेत्री ने 2018 में अभिनेत्री ने पाटेकर और तीन अन्य पर 2008 में उनके साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। तनुश्री के मुताबिक यह दुर्व्यवहार फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान की गई थी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com
बेंगलूरु | शुक्रवार | 25-07-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY
RNI No. 58061/93. Regn No.: NP/KA/BGS/2050/2018-2020 Posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026.

शहर के चिकपेट स्थित आदिनाथ जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित मुनिश्री आर्यशेखरविजयजी ने जैन रामायण ग्रंथ की व्याख्या करते हुए महासती अंजना की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि शीलवती नारी की देव भी रक्षा करते हैं।

अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ में जिनालय, दादावाड़ी, धर्मशाला संकुल हेतु भूमि का हुआ क्रय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। खरतरगच्छाधिपति आचार्यश्री जिनमणिप्रभसूरीश्वरजी की प्रेरणा से जिनदत्तकुशलसूरी खरतरगच्छ पेढ़ी द्वारा अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ में बनने जा रहे जिनालय, दादावाड़ी और भोजनशाला संकुल हेतु भूमि का क्रय किया गया। ट्रस्ट के बेंगलूरु निवासी कुशलराज गुलेच्छा ने कहा कि तीर्थ स्थल पर बन रहे जिनालय दादावाड़ी हेतु पूरे देशभर से नए ट्रस्टी बनाए गए है।

ट्रस्ट के प्रदीप श्रीश्रीमाल ने बताया कि करीबन 80 हजार फीट का विशाल भूखंड का क्रय किया जा चुका है और रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। ट्रस्ट के प्रवक्ता ललित डाकलिया ने बताया कि महाराष्ट्र के वाशिम के पास स्थित मुख्य अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ मन्दिर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित भूखंड पर जिनालय, दादावाड़ी, उपाश्रय के साथ यहां 100 रूमों की आधुनिक सुविधायुक्त धर्मशाला बनाई जाएगी तथा और योजनाओं की गुरुदेव से चर्चा करके घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर कुशलराज गुलेच्छा, प्रदीप श्रीश्रीश्रीमाल, दीपचंद बाफना, बाबूलाल लुनिया आदि ट्रस्टीजन उपस्थित थे।

जन जन के संत थे आचार्यश्री आनंदऋषि : साध्वीश्री कंचनकंवर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के जयनगर संघ के तत्वावधान में चातुर्मासार्थ विराजित उपप्रवर्तिनी कंचनकंवरजी के सान्निध्य में गतिमान आनंद जन्मोत्सव के तहत साध्वीश्री अणिमाश्रीजी ने कहा कि संतों का जीवन संघ, समाज व जनकल्याणार्थ समर्पित होता है। आनंदऋषिजी ने भी स्वार्थभाव से ऊपर उठकर हर क्षण परमार्थमय जीवन जीया है। उनके मन में दूसरों के भलाई की कामना रहती थी। आनंदऋषिजी के गुणों के गुलदस्ते में से एक भी गुण हम अपनाएंगे तो जीवन की सार्थकता होगी। साध्वीश्री दिव्ययशाजी ने कहा कि जैसे कांटों के बिना फूल नहीं होते हैं। धार के बिना तलवार नहीं होती है। नाखून के बिना शेर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गुरु के बिना जीवन सफल नहीं होता। उन्होंने कहा कि आनंद नाम में यश और आनंद वचन में रस था। उनका जीवन तप, त्याग, संयम था। प्रचार प्रसार मंत्री सागर बाफना ने बताया कि गुरुवार को औरंगाबाद से अनेक भक्तों ने साध्वियों के दर्शन किए। दोपहर में महिला मण्डल द्वारा गुरु आनंद प्रश्न मंच में 150 से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें पहला स्थान राजाजीनगर महिला मंडल, दूसरे स्थान पर जयनगर महिला मंडल रहा। संघ के अध्यक्ष दीपचन्द भंसाली ने स्वागत किया। संचालन मंत्री पदम चन्द बोहरा ने किया।

प्राचीन इतिहास भूलते जा रहे हैं लोग : आचार्य विमलसागरसूरीश्वर

गदग में ओसवाल वंश का 2482 वां स्थापना समारोह मनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गदग । गुरुवार को स्थानीय राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक संघ के तत्वावधान में जीरावला पार्श्वनाथ सभागृह में धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों का जैनधर्म में ऐतिहासिक योगदान हैं। उनकी सेवाओं को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। सभी जैन तीर्थंकर क्षत्रिय थे और महावीरस्वामी के सभी ग्यारह प्रमुख शिष्य ब्राह्मण थे। इनके अलावा अनेक महान जैनाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जैनधर्म में दीक्षित हुए थे। आचार्यश्री रत्नप्रभसूरी ने अपने बत्तीस वर्ष के कार्यकाल में चौदह लाख लोगों को मांसाहार, शराब, जुआ, अंधविश्वास, बलिप्रथा, दुराचार और व्यसनों से मुक्त कर जैन बनाया था। यह मानवीय गुणों से संपन्न सात्विक जीवनशैली का सूत्रपात था। ओसवाल वंश के 2482 वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि हम नया इतिहास तो जानते हैं, पर प्राचीन इतिहास भूलते जा रहे हैं। वर्तमान जैन समाज पर आचार्य स्वयंप्रभसूरी और आचार्यश्री रत्नप्रभसूरी का बहुत बड़ा उपकार है। ये दोनों भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के विद्याधर कुल के प्रभावशाली आचार्य थे। आचार्य स्वयंप्रभसूरी पूर्वी भारत से अपने पांच सौ शिष्यों के साथ करीब छब्बीस सौ वर्ष पर्व मारवाड़ पधारे थे। आपके सान्निध्य में तत्कालीन श्रीमाल नगर (वर्तमान में जालोर जिले के भीनमाल) में राजा जयसेन के नेतृत्व में नब्बे हजार क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने जैनधर्म अंगीकार किया था। उस समय जैनाचार्य ने क्षत्रियों के लिए पोरवाल और ब्राह्मणों के लिए श्रीमाली वंश की स्थापना की थी। आगे चलकर राजस्थान के रतनपुर के राजकुमार रत्नचूड़ ने जैन दीक्षा अंगीकार की थी।वे ही आचार्य रत्नप्रभसूरी बने, जिनके उपदेशों से श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को तत्कालीन उपकेशपुर नगर (वर्तमान में जोधपुर के पास ओसियां) में एक लाख पच्चीस हजार क्षत्रियों ने जैनधर्म स्वीकार किया था। इन नए जैनों के लिए जैनाचार्य ने ओसवाल वंश की स्थापना की थी। वर्तमान समाज में ओसवाल, पोरवाल और श्रीमाली, ये तीन मुख्य जैन जातियां हैं। जैनों में सर्वाधिक संख्या ओसवालों की हैं। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र और अमृतसिद्धि योग में गौधुलि वेला में आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी और गणि पद्मविमलसागरजी के सान्निध्य में श्रीफल अभिमंत्रित करने का मंगलमय विधान हुआ। पांच सौ से अधिक साधक इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। सचिन पोरवाल ने जानकारी दी कि श्रमण परिवार ने प्राचीन स्तोत्रों और विविध मंत्रों द्वारा यह विधान संपन्न करवाया। संघ के अध्यक्ष पंकज बाफना ने बताया कि शुक्रवार को नूतन माह के शुभारंभ के अवसर पर प्रातः पौने नौ बजे महामांगलिक की जानकारी दी।

कर्नाटक में गड़बड़ी के 100 प्रतिशत सबूत, आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता : राहुल गांधी

बेंगलूरु/नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी करने देने के ''100 प्रतिशत सबूत'' हैं और यदि आयोग यह सोचता है कि वह इससे बच जाएगा, तो यह उसकी ग़लतफ़हमी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। उन्होंने कर्नाटक के निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बारे में पूछे जाने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। आज उन्होंने कुछ बयान दिया है, यह पूरी तरह से बकवास है। सच तो यह है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है।

राहुल गांधी ने कहा, ''अब हमारे पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की अनुमति देने के 100 प्रतिशत ठोस सबूत हैं। 90 प्रतिशत नहीं।

सद्गुरु के समागम से सन्मार्ग की प्राप्ति होती है : आचार्यश्री प्रभाकरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के महालक्ष्मी लेआउट स्थित चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में चातुर्मासार्थ विराजित आचार्यश्री प्रभाकरसूरीश्वरजी व साध्वी तत्वत्रयाश्रीजी की निश्रा में अपने प्रवचन में आचार्यश्री ने कहा कि जीवन में परिस्थितियों, ऋतुओं, मनुष्यों, देवों, तिर्यंचों आदि की प्रतिकूलता के कारण जो कष्ट आते हैं उनमें मूल कारण तो साधक के अपने पूर्वकृत कर्म ही होते हैं। जीवन में कर्म सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। आचार्यश्री ने कहा कि आत्मा पुण्य-पाप का विवेक नहीं करती। मात्र स्वदेह में ही आसक्त रहती है, दूसरे के सुख दुख का विचार नहीं करती। इस प्रकार पाप आचरण से आत्मा नए कर्मों का बंध करते हुए अनेक दुख का अनुभव करती है। उन्होंने कहा कि सदगुरु के समागम से सन्मार्ग की प्राप्ति होती है, आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। तप धर्म के निरंतर अभ्यास से आत्मा देह के भयंकर दुखों में भी दृष्टा मात्र बन कर रहती है। सम्यक तप से आत्मा देह के नाश के बावजूद दुख का अनुभव नहीं करती। उन्होंने कहा कि तप धर्म के अभ्यास से व्यक्ति सहनशील बनता है और देह के दुखों को हंसते हुए सहन करता है। तप धर्म का दूसरा उद्देश्य इंद्रियजय है। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सभी राग और द्वेषों के त्याग से अपने शुद्ध आत्मस्वभाव में लीन होना उत्तम तप है। व्यावहारिक दृष्टि से अनशन व्रतादि तप हैं। जैन दर्शन में तप और तपस्या को बहुत महत्व दिया गया है। भोगवादी दृष्टिकोण वाले मनुष्य हमेशा दुखी ही रहते हैं। ठीक इसके विपरीत जो जीवन में स्वयं ही तप को अपनाता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। सभा में मुनिश्री महापद्मविजयजी, पद्मविजयजी, साध्वी तत्वत्रयाश्रीजी, गोयमरत्नाश्रीजी व परमप्रज्ञाश्रीजी उपस्थित थे।

दुख अपने स्वयं के कर्म के कारण आता है : साध्वी मयूरयशाश्री

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । शहर के सुमतिनाथ जैन संघ मागड़ी रोड के तत्वावधान में चातुर्मास विराजित साध्वी मयूरयशाजी ने धर्मरत्न प्रकरण का वाचन करते हुए श्रावक के 21 गुणों के अंतर्गत दूसरे रूपवान गुण का वर्णन करते हुए बताया कि अगर हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाए तो दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। निमित्त बिना कार्य नहीं होता और कार्य बिना निमित्त नहीं होता। जैसे कुर्सी से ठोकर लग जाए तो कुर्सी की गलती नहीं होती, हमारी गलती है, वैसे ही आने वाला दुख भी उस कुर्सी के समान है यानी दुख अपने स्वयं के कर्म के कारण आता है। हमें किसी को सुधारना हो तो द्वेषमुक्त फरियाद करनी चाहिए और प्रेम से प्रेम देना चाहिए। हमें किसी का दोष नहीं खोजना चाहिए और किसी का दोष भी नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को सब फलों का रस प्रिय हो सकता है लेकिन निंदा रस सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए व्यक्ति को दूसरों की निंदा में रस होता है। दुनिया को बिगाड़ने वाला मोबाइल है। निंदा करना भी एक प्रकार का नशा है। किसी की निंदा की बात भी नहीं सुननी चाहिए। हमेशा अच्छा सुनो और अच्छे बनो।

गुरु ज्ञान की नौका होते हैं जो हमें भवसागर पार कराते हैं : साध्वीश्री इन्दुप्रभा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्थानीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, अलसूर के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित प्रवचन में साध्वी इंदुप्रभाजी ने कहा कि न हमारा प्रभाव, न बल और न देवी देवता हमें मृत्यु से बचा सकते हैं। मृत्यु के वक्त हम लाचार असहाय हो जाते हैं। ज्ञानी इस सत्य को स्वीकार कर पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं क्योंकि मात्र धर्म की शरण ही हमें दुर्गति से बचा सकती है। हम पहले आत्मा की चिंता करें। संसार में रहते हुए और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने को नही भूलें, क्योंकि हमारी इस लापरवाही ने ही हमें अनंत काल से भटकाया है। प्रवचन को प्रारंभ करते हुए साध्वी वृद्धिप्रभा जी ने कहा कि सभी जीवों में मुक्ति की योग्यता और शक्ति है। हमने प्रमाद में उस शक्ति को दबा दिया है और आवरण बना लिया है। प्रभु की वाणी श्रवण का संयोग मिल गया है और यह अनंत बंधनों को तोड़ने का स्वर्णिम मौका है। मुक्ति की प्यास लगनी चाहिए और प्यास भी ऐसी कि मंजिल तक रुकना नहीं चाहिए। प्रभु की वाणी हमें संसार सागर में तैरना सिखाती है और गुरु ज्ञान की नौका होते हैं। अलसूर संघ के मंत्री अभय कुमार बांठिया ने चातुर्मास के पिछले पंद्रह दिनों की उपलब्धियों की जानकारी दी। महेंद्र रांका ने गुरु ज्येष्ठ पुष्कर समिति की ओर से आयोजित होने वाली भिक्षु दया की जानकारी दी। साध्वी शशिप्रभाजी ने मंगलपाठ सुनाया।

शाकद्वीपीय महिलाओं ने की शिवपूजा और झूला झूलकर मनाई हरियाली अमावस्या

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्थानीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज की माध्यम महिला मंडल द्वारा गुरुवार को जेपी नगर स्थित सूर्य मंदिर में महादेव की आराधना के साथ श्रावण माह की हरियाली अमावस्या पर सावन मेले का आयोजन चंद्रा शर्मा एवं संतोष शर्मा के नेतृत्व में किया गया। सुबह सर्वप्रथम कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने मंदिर की परिक्रमा कर गंगाजल द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। माध्यम महिला मंडल की महिलाओं को अध्यक्ष संतोष शर्मा द्वारा हरी चूड़ियां एवं श्रृंगार सामग्री भेंट की गई। मंदिर परिसर में पंडित श्रेयांश पाण्डेय के आचार्यत्व में विधिविधान से मंत्रोच्चार पूर्वक महिलाओं ने पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर पंचोपचार पूज की। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर सभी महिलाओं ने एक-दूसरे को झूला झुलाकर शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर अनेक महिलाएं उपस्थित थीं।

जीवन में कर्म के अनुसार ही मिलता है फल : मुनिश्री आर्यशेखरविजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के चिकपेट स्थित आदिनाथ जैन संघ में चातुर्मासार्थ विराजित मुनिश्री आर्यशेखरविजयजी ने जैन रामायण ग्रंथ की व्याख्या करते हुए महासती अंजना की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि शीलवती नारी की देव भी रक्षा करते हैं। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु यह निश्चित है और इन तीनों से कोई बचाने वाला है शील। मुनिश्री ने कहा कि कुत्ते को कोई पत्थर मारे तो कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है परंतु सिंह को पत्थर मारा जाए तो सिंह पत्थर के पीछे नहीं, बल्कि पत्थर मारने वाले के पीछे भागता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि पत्थर तो निमित्त है, निमित्त के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होता अपितु कारण की खोज करनी चाहिए। कर्म सत्ता कहती है कि जिसका जैसा पुण्य होता है वैसा उसे सत्कार मिलता है। संतश्री ने कहा कि दूसरों के दोष दिखें तो आंख बंद कर लेनी चाहिए। आंखों के अंधेपन और कानों के निंदापन से हमें बचना चाहिए। मुनिश्री ने कहा कि अच्छी स्थिति में धर्म कर लेना चाहिए।

संवाद करने से ज्ञान बढ़ता है : संतश्री ज्ञानमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के सुमतिनाथ जैन संघ यलहंका में विराजित आचार्यश्री हस्तीमलजी के शिष्य श्री ज्ञानमुनिजी ने कहा कि प्रभु महावीर की वाणी को आगम के रूप में लिखा गया था और हमारे गुरु भगवंतों ने थोकड़ों (सार) के रूप में उनका निचोड़ हमें दिया है।

इन थोकड़ों को समयकत्व के सड़सठ बोल कहते हैं, यह थोकड़े होते बहुत छोटे हैं परंतु उनमें ज्ञान का रस बहुत ही ज्यादा होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं अगर कोई ज्ञानी मिले तो उनसे चर्चा करें, संवाद करें विवाद नहीं। संवाद करने से ज्ञान बढ़ता है लेकिन विवाद करने से सिर्फ अपवाद होता है।

मुनिश्री ने कहा कि प्रभु महावीर ने बताया है कि जो पाप करता हैं, हिंसा कृत्य करता हैं उसे सोते रहना चाहिए और जो धर्म, दान, पुण्य में अग्रसर हैं उसे जागते रहना चाहिए। दुख में मित्रों के साथ आगे रहना चाहिए और सुख में सबसे पीछे रहना चाहिए। गुरुवार को मनोजकुमार बोहरा ने 7 उपवास के पच्चखान ग्रहण किया। सभा में अध्यक्ष प्रकाशचंद कोठारी ने सभी का स्वागत किया।

महामंत्री मनोहरलाल लुकड़ ने सभा का संचालन करते हुए बताया कि आगामी रविवार को आचार्य हस्तीमलजी, आचार्यश्री शोभाचंदजी की पुण्यतिथि और श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर आचार्यश्री आनंदऋषिजी की जयंती मनाई जाएगी।

शाश्वत सुख का राजपथ है लोगस्स : साध्वीश्री पुण्ययशा

सजोड़े लोगस्स कल्प अनुष्ठान आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के आरआर नगर स्थित तेरापंथ भवन में चातुर्मासार्थ विराजित साध्वी पुण्ययशाजी के सान्निध्य में लोगस्स कल्प सप्ताह के अन्तर्गत गुरुवार को सजोड़े लोगस्स कल्प अनुष्ठान का विशेष प्रयोग करवाया गया। साध्वीश्री ने कहा कि लोगस्स में जीवन निर्माण, विकास तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आत्मकर्तृत्ववाद का वर्णन है। सीमित शब्दों में असीमित व्यक्तित्वों की गौरवगाथा के अमित हस्ताक्षर व मंत्राक्षर इस स्तुति में विद्यमान है। सचमुच लोगस्स शाश्वत सुख का राजपथ है। इस स्तवन से समाधि का द्वार खुलता है, प्रज्ञा अनावृत्त होती है, सूक्ष्म शक्तियों की जागृति के साथ-साथ ज्ञान-आनंद व तेजस शक्ति प्रकट होती है। ज्ञान, आनंद व तेज ये तीनों महाशक्तियाँ हमारे अपने भीतर ही है और तीनों का स्रोत एक आत्मा है। तेरापंथी सभा के अध्यक्ष राकेश छाजेड़ ने सभी का स्वागत करते हुए साध्वीश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। अनुष्ठान में 113 जोड़ों सहित लगभग 300 लोगों की उपस्थिति रही। अनुष्ठान में लोगस्स के प्रत्येक पद के साथ मंत्र गर्भित बीजाक्षरों के साथ जप एवं ध्यान का प्रयोग करवाया गया। इस मौके पर हनुमन्तनगर से भी बड़ी संख्या में श्रावक उपस्थित थे। सभा, तेयुप एवं महिला मंडल के सदस्यों ने व्यवस्था संभाली।

ट्रेड शो में सौ करोड़ से अधिक का हुआ व्यवसाय

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक इनरवियर एसोसिएशन (किया) के तत्वावधान में पैलेस मैदान के गायत्री विहार में आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक मेला 'दि इनर स्टोरी' का गुरुवार को समापन हुआ। समापन के मौके पर व्यापारियों ने अगले वर्ष नए अंदाज में नए जोश के साथ मिलने का वादा कर विदाई ली। तीन दिवसीय मेले के दौरान 6 हजार से अधिक व्यापारियों ने दौरा लिया और बुकिंग कराई। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप जैन ने बताया कि व्यापार अनुबंध की दृष्टि से मेक इन इंडिया पर आधारित मेले में सौ करोड़ रुपए से अधिक के व्यापार अनुबंध किए गए हैं। गत वर्ष ये आंकड़ा करीब 90 करोड़ रुपए का था। उन्होंने बताया कि आगामी सीजन के दृष्टिगत माल की बुकिंग की गई है।

उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए 'किया' की पूरी टीम गत एक माह से रात दिन लगी हुई थी, यह उसी का सकारात्मक परिणाम है कि व्यापार अनुबंध सौ करोड़ को पार कर सका है। बुधवार को सभी प्रतिभागियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया था।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अश्विन सेमलानी ने कहा कि 'किया' का यह मेला पूरी तरह मेक इन इंडिया की थीम पर आधारित था। मेले में 70 स्टॉल लगाई गई थीं और व्यापारियों का अच्छा सहयोग मिला। समापन समारोह में सभी कमेटियों के सदस्यों का सम्मान किया गया और टाइटल प्रायोजक टेसुटी इंडस्ट्रीज के प्रमुख रमेश कोठारी भी मौजूद थे। इस मौके पर सचिव रविन्द्र बंबोली, कोषाध्यक्ष प्रकाश एच जैन, संयुक्त सचिव शैंकी एम जैन, जिनेन्द्र कुमार, संयुक्त कोषाध्यक्ष विनोद चौहान और अलावा प्रदर्शनी समन्वयक महेन्द्र जैन, प्रदर्शनी कमेटी के राजेश चोपड़ा, मनीष ए. जैन, माधुराम खादव, गौरव शर्मा, महीपाल टी. जैन, मूल सिंह राजपुरोहित समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com